अपने धर्म का पालन करना
ही सबसे बड़ा धर्म है।
- श्रीमद् भगवतगीता

The Public Hub

पेज 6 | स्पोर्ट्स

वर्ष 1 अंक : 6 ₹ 4.00 पृष्ठ-8

www.thepublichub.in

जयपुर
बुधवार 11 मार्च, 2026

राजस्थान में रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुसीबत... | 3

'मॉडल बिल्डिंग विनियम-2025' का खुला उल्लंघन

जयपुर के रिहायशी इलाकों में चल रहे 'अवैध' पीजी

जयपुर (विशेष संवाददाता)। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे शिक्षा का हब माना जाता है, के पॉश और रिहायशी इलाकों में अवैध हॉस्टल और पेइंग गेस्ट का एक संगठित सिंडिकेट बेखौफ संचालित हो रहा है। रिहायशी मकानों को अवैध रूप से व्यावसायिक परिसरों में बदलकर सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक सीधी शिकायत पहुंची है। शिकायत में शहर के हजारों अवैध हॉस्टलों और पीजी पर तत्काल सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की मांग की गई है।

रिहायशी इलाकों में कमर्शियल खेल, नियमों की उड़ रही धज्जियां : जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के नियमों को ताक पर रखकर यह खेल चल रहा है। रिहायशी पट्टों वाले भूखंडों पर बिना 'भू-उपयोग परिवर्तन' कराए पूरी तरह से कमर्शियल गतिविधियां चलाई जा रही हैं। ये संचालक न तो कमर्शियल दरों पर बिजली-पानी का बिल भर रहे हैं और न ही सरकार को कोई टैक्स दे रहे हैं। आरोप है कि यह सब कुछ संबंधित विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है, जो आँखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं।

'मॉडल बिल्डिंग विनियम-2025' का खुला उल्लंघन : शिकायत में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए 'मॉडल बिल्डिंग विनियम-2025' का हवाला देते हुए बताया गया है कि बड़े शहरों में हॉस्टल संचालन के लिए कड़े नियम हैं। नियमों के मुताबिक, हॉस्टल के लिए कम से कम 500 वर्ग मीटर का भूखंड होना चाहिए और वह न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित होना चाहिए। लेकिन जयपुर में संकरी गलियों और छोटे भूखंडों पर बहुमंजिला हॉस्टल तान दिए गए हैं, जो न केवल अवैध हैं बल्कि हादसे को न्योता दे रहे हैं।

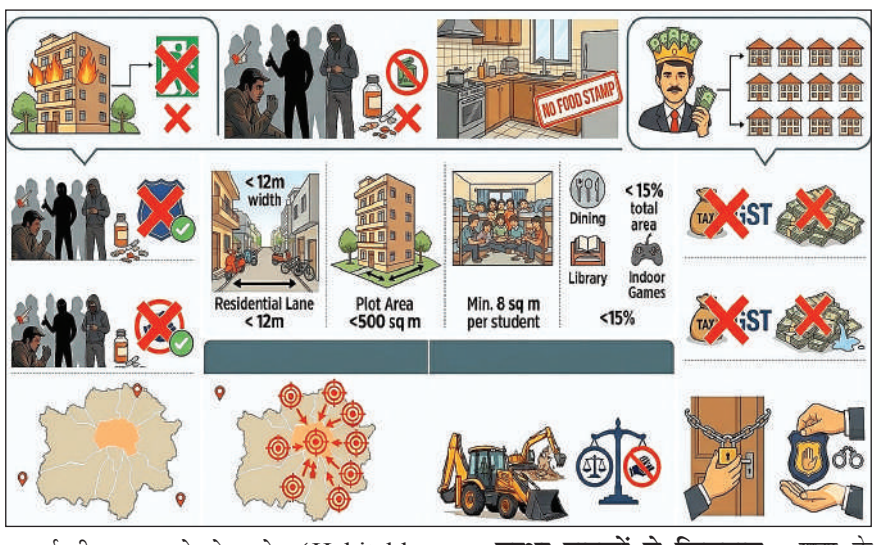

मुनाफाखोरी के लालच में छात्रों के जीवन स्तर से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। नियमों के अनुसार, हॉस्टल में प्रति छात्र/व्यक्ति कम से कम

8 वर्ग मीटर का रहने योग्य क्षेत्र (Habitable Room Area) होना अनिवार्य है। इसके अलावा, हॉस्टल के कुल क्षेत्रफल का 15% हिस्सा कॉमन सुविधाओं जैसे डाइनिंग एरिया, किचन, लाइब्रेरी और इंडोर गेम्स के लिए आरक्षित रखना होता है। शिकायत में दावा किया गया है कि जयपुर के अधिकांश पीजी और हॉस्टल इन मानकों को पूरा नहीं करते और छात्रों को बेहद संकरे कमरों में ठूंसा जा रहा है।

सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ : शहर के अधिकांश पीजी और हॉस्टलों के पास फायर एनओसी तक नहीं है। आगजनी की घटना होने पर यहां से निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। इसके अलावा, छात्रों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता जांचने वाला FSSAI लाइसेंस भी इन संचालकों के पास नहीं है। बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहे इन संस्थानों पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है।

सीलिंग और ध्वस्तीकरण की मांग

शिकायत में राज्य सरकार से मांग की गई है कि ऐसे सभी अवैध हॉस्टल और पीजी को चिन्हित कर उनके खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। साथ ही, 'मॉडल बिल्डिंग विनियम-2025' की पालना सुनिश्चित करवाई जाए और दोषी अधिकारियों व संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। शिकायतकर्ता एडवोकेट चंद्रशेखर कच्छावा ने 31 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, नगरीय विकास मंत्री, आयकर आयुक्त और जयपुर पुलिस कमिश्नर समेत तमाम उच्च अधिकारियों को यह विस्तृत परिवाद (शिकायत) भेजा है और तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

अपराधियों और नशे के सौदागरों की शरणस्थली

मामले का सबसे खतरनाक पहलू सुरक्षा से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि पीजी और हॉस्टल की आड़ में पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। इसका फायदा उठाकर आपराधिक किस्म के लोग, ड्रग्स तस्कर और सट्टा कारोबारी इन जगहों पर पनाह ले रहे हैं। बिना पहचान के रह रहे ये तत्व बेखौफ होकर स्मैक, अफीम और गांजे का व्यापार कर रहे हैं और पुलिस की रडार से बचे रहते हैं।

टैक्स चोरी का बड़ा खेल : एक-एक मालिक के पास 15-15 हॉस्टल

शिकायत में एक बड़े 'नेक्सस' का पर्दाफाश किया गया है। कुछ बड़े व्यापारी 15-15 हॉस्टल और पीजी चला रहे हैं, लेकिन वे इनकम टैक्स और जीएसटी (जीएसटी) के दायरे से बाहर हैं। वे न तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और न ही सरकार को टैक्स देते हैं। यह पूरा सिंडिकेट करोड़ों रुपये की काली कमाई कर रहा है और सरकारी राजस्व (राजकोष) को भारी नुकसान पहुंचा रहा है।

इन इलाकों में सबसे ज्यादा सक्रिय है माफिया

जयपुर के लगभग हर प्रमुख इलाके में यह धंधा फैला हुआ है। शिकायत में विशेष रूप से मालवीय नगर, प्रताप नगर, जगतपुरा, पृथ्वीराज नगर, विद्याधर नगर, लाल कोठी, गुर्जर की थड़ी, श्याम नगर, महेश नगर, गोपालपुरा, दुर्गापुरा, बापू नगर, वैशाली नगर, राजापार्क और सी-स्कीम जैसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। यहां रिहायशी मकानों और फ्लैटों में अवैध रूप से हॉस्टल संचालित हो रहे हैं।

सात समंदर पार की जंग और राजस्थान की रसोई पर संकट

ईरान और इजरायल के बीच गहराता तनाव अब केवल अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि इसकी तपिश राजस्थान के व्यावसायिक चूल्हों तक पहुँच गई है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और सप्लाई चेन में आए व्यवधान का सीधा असर प्रदेश के एलपीजी सेक्टर पर दिखने लगा है, जो चिंता का विषय है।

सप्लाई पर 'ब्रेक' और बाजार में हड़कंप : तेल कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) द्वारा डीलर्स को भेजे गए आपातकालीन संदेश, जिनमें व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति अगले आदेश तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं, ने प्रदेश के व्यापारिक जगत में खलबली मचा दी है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन और खान-पान उद्योग की अहम भूमिका है। ऐसे में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसे शहरों के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट और मिठाई के कारोबार पर संकट के बादल मंडराना तय है।

शादियों के सीजन में 'कैटरिंग' की बढ़ी धड़कनें : सबसे ज्यादा प्रभावित कैटरिंग व्यवसाय होने की संभावना है, क्योंकि मार्च और अप्रैल में शादियों का सीजन अपने चरम पर है। हजारों लोगों का खाना तैयार करने की जिम्मेदारी निभाने वाले कैटरर्स अब भट्टी और कोयले जैसे पुराने विकल्पों की तलाश में हैं, जो आधुनिक मांग के सामने नाकाफी साबित हो सकते हैं।

चुप्पी बढ़ा रही है अनिश्चितता : इस गंभीर स्थिति पर गैस कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयकों की चुप्पी और भी अधिक चिंताजनक है। आधिकारिक स्पष्टीकरण के अभाव में बाजार में अनिश्चितता बढ़ रही है, जिससे कालाबाजारी और कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि अभी केवल व्यावसायिक सिलेंडरों पर रोक की बात सामने आई है, लेकिन यदि युद्ध लंबा खिंचता है, तो इसका असर घरेलू रसोई तक पहुँचना भी तय माना जा रहा है।

निष्कर्ष : सरकार और तेल कंपनियों को चाहिए कि वे इस संकट पर पारदर्शिता बरतें और वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश की आम जनता और छोटे व्यापारियों को इस वैश्विक युद्ध की स्थानीय कीमत न चुकानी पड़े।

- राखी सिंह, कार्यकारी संपादक

यूपीएससी-2025 : राजस्थान के डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने रचा इतिहास

__जयपुर (विशेष संवाददाता)।__ संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 6 मार्च को सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार मरुधरा की माटी का गौरव पूरे देश में चमका है। कोटा के रावतभाटा के निवासी डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया पहली रैंक हासिल कर राजस्थान का नाम रोशन किया है। अपनी मेधा और कड़े परिश्रम के दम पर अनुज ने यह साबित कर दिया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, तो कोई भी बाधा राह नहीं रोक सकती। परिणाम जारी होने के बाद से ही उनके घर और पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है।

AIIMS से डॉक्टरी और अब देश की सर्वोच्च सेवा : *डॉ. अनुज की शैक्षणिक यात्रा किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान एम्स (AIIMS) जोधपुर से साल 2023 में एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री पूरी की थी। चिकित्सा क्षेत्र की बारीकियों को समझने के बाद उन्होंने समाज के व्यापक स्तर पर बदलाव लाने के उद्देश्य से*

प्रशासनिक सेवाओं का रुख किया। उनके पिता के.बी. अग्निहोत्री राजस्थान परमाणु बिजलीघर में कार्यरत हैं और माता मंजू अग्निहोत्री एक गृहिणी हैं। अनुज की यह सफलता इसलिए भी विशेष है क्योंकि उन्होंने यह मुकाम एक पूर्णकालिक अधिकारी की जिम्मेदारी निभाते हुए हासिल किया है। अनुज वर्तमान में DANICS कैडर के तहत दिल्ली में एसडीएम (SDM) के पद पर तैनात हैं।

टाइम मैनेजमेंट : *ऑफिस की व्यस्तता और प्रशासनिक चुनौतियों के बीच उन्होंने समय निकालकर पढ़ाई जारी रखी और अंततः अपना 'IAS' बनने का सपना पूरा किया।*

प्रदेश में बिना मान्यता चल रहे 25000 स्कूलों का मामला

एक्शन की तैयारी : शिक्षा मंत्री दिलावर ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश

जयपुर (विशेष संवाददाता)। प्रदेश में बिना सरकारी मान्यता के चल रहे 25000 ज्यादा निजी स्कूलों के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिना मान्यता धड़ल्ले से चल रहे इन निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तत्काल प्रभाव से उच्च स्तरीय जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद अब निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इस मामने में जांच को लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी ओर राज्य सरकार की मान्यता के बिना चल रहे ऐसे निजी स्कूलों में अब खलबली मच गई है।

क्या है पूरा मामला ?

विभागीय सूत्रों के अनुसार, प्रदेश भर में हजारों ऐसे स्कूल संचालित हो रहे हैं जिनके पास शिक्षा विभाग की वैध मान्यता (Recognition) नहीं है। प्रदेश में 25 हजार से ज्यादा निजी स्कूल केंद्रीय बोर्ड (CBSE) और अन्य बोर्डों की संबद्धता की आड़ में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं, जबकि उनके पास राज्य सरकार से इन कक्षाओं के संचालन की मान्यता ही नहीं है। प्रदेश में 25,000 स्कूलों का बिना मान्यता के चलना एक बड़ा प्रशासनिक फेलियर है।

दरअसल प्रदेश में निजी संस्थानों द्वारा स्कूलों के संचालन में नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, जिसको लेकर कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा कई बार आदेश भी जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार, राज्य में संचालित ऐसे गैर-सरकारी विद्यालय, जो राजस्थान बोर्ड (RBSE) के अलावा अन्य बोर्ड (CBSE) से संबद्धता रखते हैं, उन्हें अपने संचालन कक्षा स्तर के अनुसार राज्य विभाग से मान्यता लेना अनिवार्य है लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश के 25 हजार से ज्यादा स्कूल केवल कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता लेकर बैठे हैं। वे कक्षा 9 से 12 तक के संचालन के लिए CBSE या अन्य बोर्ड से एफिलिएशन तो ले लेते हैं, लेकिन राज्य शिक्षा विभाग से एनओसी (NOC) और क्रमोन्नति (Recognition) नहीं लेते है। निजी संस्थानों द्वारा स्कूल CBSE की संबद्धता को ही मान्यता मानकर मनमाने तरीके से शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं।

नियमों की निजी स्कूल नहीं कर रहे पालना

शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक (शिविरा-माध्य/पीएसपी-सी/अ-2/60567/के.मा.शि.बो/ वो-1/2023-2024/29, दिनांक 22.12.2022) में स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि अन्य बोर्ड से

The Public Hub Exclusive Report : CBSE की आड़ में बड़ा खेल
प्रदेश के 25,000 निजी स्कूलों के पास नहीं है राज्य की मान्यता, कागजों में सिमटा शिक्षा विभाग

संबद्धता लेने से पहले उस कक्षा स्तर की राज्य से मान्यता लेना अनिवार्य है। यदि स्कूल के पास मान्यता नहीं है, तो उसे केवल उसी कक्षा तक एनओसी मिलेगी जिसकी मान्यता उसके पास है। उच्च कक्षा की संबद्धता लेने से पूर्व शिक्षा विभाग से क्रमोन्नति लेना अनिवार्य होगा, लेकिन निजी स्कूलों द्वारा इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। निजी स्कूलों की मनमानी तो इस कदर है कि शिक्षा विभाग से मान्यता लेना तो बहुत दूर की बात है, पीएसपी पोर्टल पर ही अपनी जानकारी अपडेट नहीं कर रहे हैं।

राज्य सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान

निजी संस्थानों द्वारा खुलेआम चल रहे इस खेल एवं नियमों की अनदेखी से राज्य सरकार को दो बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। पहला तो निजी संस्थानों द्वारा कक्षा 9 से 12 तक की मान्यता नहीं लेने से राज्य सरकार को हर साल भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर से इन कक्षाओं का राज्य सरकार के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, इसलिए इनकी मॉनीटरिंग नहीं हो पा रही है। ऐसे में ये निजी स्कूल राज्य सरकार के नियमों के प्रति जवाब देही से बचकर निकल जाते हैं।

अमायरा केस इसका ज्वलंत उदाहरण

जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल में हुई छात्रा अमायरा की आत्महत्या का मामला इसका ज्वलंत उदाहरण है। अमायरा केस में एक 9 साल की बच्ची ने स्कूल प्रशासन की ज्यादतियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और CBSE ने नीरजा मोदी स्कूल की संबद्धता रद्द कर दी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि राज्य सरकार कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सकी। इसका कारण यह था कि स्कूल के पास राज्य सरकार की मान्यता ही नहीं थी। यदि स्कूल राज्य सरकार की मॉनिटरिंग में होता, तो शायद यह हादसा रोका जा सकता था और स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती थी। राज्य की मॉनिटरिंग न होने के कारण ही प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है और स्कूली बच्चों और अभिभावकों को मानसिक और वित्तीय परेशानियां उठानी पड़ रही है, और शिक्षा विभाग मूकदर्शक बनकर यह सारा तमाशा देख रहा है।

'मिस्टर इंडिया' बने पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल | पिछले 20 दिनों से कानून की नजरों से बचकर भाग रहे अग्रवाल को पकड़ने के लिए एसीबी का 'सर्च' अभियान जारी

विदेश नहीं, रसूखदारों के 'सेफ हाउस' में छिपे हैं घोटाले के 'सुपर खिलाड़ी'!

जयपुर (विशेष संवाददाता)। राजस्थान के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचाने वाले बहुचर्चित JJM भ्रष्टाचार कांड के मुख्य आरोपी सुबोध अग्रवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 20 दिनों से कानून की नजरों से बचकर भाग रहे अग्रवाल को पकड़ने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का बड़ा 'सर्च' अभियान जारी है।

एसीबी की जांच के बाद जल जीवन मिशन (जेजेएम) के नाम पर राजस्थान की जनता की प्यास से जुड़ी पेयजल योजनाओं के पैसों को 'डकारने' वाले नेताओं, अधिकारियों व इंजीनियर्स के चेहरों से नकाब उतरना शुरू हो गया है। हालांकि जेजेएम घोटाले के मुख्य किरदार और पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल अभी भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की आंखों में धूल झोंककर फरार हैं। '**The Public Hub**' की पड़ताल में सामने आया है कि 'साहब' विदेश नहीं भागे हैं, बल्कि देश की ही माटी पर चूहे-बिल्ली का खेल खेल रहे हैं।

सीसीटीवी फुटेज में आया सामने, एयरपोर्ट पर नहीं मिली 'एंट्री'

पिछले कई दिनों से गलियारों में चर्चा थी कि सुबोध अग्रवाल सरहद पार कर चुके हैं। लेकिन एसीबी ने जब जयपुर और दिल्ली एयरपोर्ट के पिछले एक महीने के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो 'साहब' कहीं नजर नहीं आए। एसीबी की ओर से पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल के विदेश भागने की संभावनाओं को देखते हुए 18 फरवरी को ही 'लुकआउट' नोटिस जारी कर दिया था, जो कि कारगर साबित हुआ।

देशव्यापी घेराबंदी, दिल्ली से मुंबई तक रडार पर ठिकाने : उप महानिरीक्षक (डीआईजी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) की सीधी निगरानी में गठित इन टीमों ने राजस्थान के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में डेरा डाल रखा है। जांच का दायरा केवल सरकारी आवासों तक सीमित नहीं है, बल्कि फार्म हाउस, लग्जरी होटलों और रिश्तेदारों के आलीशान बंगलों की भी तलाशी ली जा रही है। एसीबी टीमों ने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, नोएडा, फरीदाबाद, प्रयागराज और मेरठ सहित कई प्रमुख शहरों में दबिश दी गई थी, लेकिन अभी तक सुबोध अग्रवाल एसीबी की पकड़ से दूर है। इस दौरान एसीबी टीमों ने दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी व न्यू मोती बाग, मुंबई के मालाबार हिल व जुहू जैसी हाई-प्रोफाइल लोकेसन्स पर दबिश देने के साथ जयपुर के सी-स्कीम व निर्माण नगर स्थित आवासों पर लगातार नजर रखे हुए हैं।

रिश्तेदारों और करीबियों पर कसा शिकंजा

एसीबी ने सुबोध अग्रवाल को शरण देने और भागने में मदद करने के संदेह में उनके तीन भाइयों और एक करीबी मित्र को बुलाकर भी पूछताछ की है। वहीं एसीबी की टीमों द्वारा अब तक राजस्थान, नोएडा (यूपी) और महाराष्ट्र में सुबोध अग्रवाल के करीबियों, रिश्तेदारों और पुराने ड्राइवरों समेत 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पूछताछ के दौरान एसीबी उन 'मददगारों' की पहचान कर रही हैं जो फरार अधिकारी को छिपने के लिए जगह और संसाधन मुहैया करा रहे हैं। सुबोध अग्रवाल ने अपने सभी मोबाइल और डिजिटल डिवाइस बंद कर रखे हैं ताकि लोकेशन ट्रेस न हो सके। सूत्रों का दावा है कि सुबोध अग्रवाल इस समय किसी रसूखदार सफेदपोश के 'सेफ हाउस' में छिपे हैं और वहीं से नामी वकीलों के जरिए 'अग्रिम जमानत' की बिसात बिछा रहे हैं।

मुख्यमंत्री निवास पर होली का उल्लास

सीएम भजनलाल शर्मा आरएसी जवानों संग थिरके, प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना

ब्रज के भजनों और शेखावाटी के चंग की थाप पर झूमी राजधानी, सीएम ने सपत्नीक आमजन के साथ खेली फूलों की होली

जयपुर (विशेष संवाददाता)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री निवास पर होली और होलिका दहन का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने न केवल विधिवत पूजा-अर्चना की, बल्कि प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने आरएसी के जवानों और प्रदेशभर से आए आमजन के साथ थिरकते हुए आपसी भाईचारे और कटुता भुलाकर खुशियां बांटने का संदेश दिया।

राज राजेश्वरी मंदिर में होलिका दहन : सोमवार मध्यरात्रि के बाद मुख्यमंत्री निवास स्थित राज राजेश्वरी मंदिर प्रांगण में होलिका दहन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच मुख्यमंत्री ने सपत्नीक अग्नि प्रज्वलित की और परिक्रमा कर प्रदेश की उन्नति, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की मंगलकामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहे।

होली महोत्सव 2026: मुख्य आकर्षण

बुधवार को आयोजित होली मिलन समारोह में प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता एक ही छत के नीचे नजर आई ब्रज की होली ब्रज से आए कलाकारों ने फूलों की होली और भजनों के माध्यम से समां बांध दिया। शेखावाटी का धमाल फतेहपुर (सीकर) की गो वत्स फाग मंडली ने चंग के साथ पारंपरिक धमाल मचाया, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी सुर मिलाया। जनता का प्रेम:प्रदेशभर से आए हजारों लोगों ने मुख्यमंत्री को साफा पहनाया और हाथ से बनी पिचकारी व जयपुर के प्रसिद्ध 'गुलाल गोटा' भेंट किए।

'कटुता भुलाकर मनाएं पर्व' - मुख्यमंत्री का संदेश

जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, 'होली रंगों और प्रेम का त्योहार है। हमें पुरानी कटुता को भुलाकर एक-दूसरे के साथ खुशियां बांटने का संकल्प लेना चाहिए।' मुख्यमंत्री ने पूरी आत्मीयता के साथ सभी पर फूलों की वर्षा की और उपस्थित जनसमूह का अभिनंदन किया।इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा सहित कई कैबिनेट मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जब चंग की थाप पर थिरके मुख्यमंत्री

उत्सव का सबसे आकर्षण केंद्र राजस्थान पुलिस की आरएसी (आरएसी) बटालियन के जवानों की प्रस्तुति रही। चंग की थाप पर जब जवानों ने फाल्गुनी गीत और पारंपरिक नृत्य शुरू किया, तो मुख्यमंत्री खुद को रोक नहीं पाए और उनके बीच पहुंचकर नृत्य किया।

जवानों के साथ मुख्यमंत्री की इस आत्मीयता ने कार्यक्रम में उत्साह का संचार कर दिया।

जयपुर में पुलिस की 'खाकी होली' जवानों ने डीजीपी को कंधों पर उठाकर किया डांस, कमिश्नर भी थिरके

जनता की सुरक्षा के बाद अब पुलिस की बारी; चांदपोल पुलिस लाइन और थानों में गुलाल के साथ मना जश्न

जयपुर (विशेष संवाददाता)। गुलाबी नगरी में आमजन की होली को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के बाद, अब जयपुर पुलिस ने अपने पारंपरिक अंदाज में रंगों का पर्व मनाया। चांदपोल स्थित पुलिस लाइन में आयोजित 'पुलिस होली' के दौरान एक दुर्लभ और उत्साहजनक दृश्य देखने को मिला, जब पुलिसकर्मियों ने अपने मुखिया, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा को सम्मान और खुशी के साथ अपने कंधों पर उठा लिया। डीजीपी ने भी खाकी के गौरव को बनाए रखते हुए जवानों के साथ होली के गीतों पर जमकर नृत्य किया, जिससे पूरे परिसर का माहौल उल्लास से भर गया।

अफसर और जवान रंगों में मिट गई दूरियां : चांदपोल पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में न केवल डीजीपी, बल्कि डीजी संजय अग्रवाल और जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल भी मौजूद रहे। कमिश्नर सचिन मित्तल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने डीजे की धुन पर जवानों के साथ थिरकते हुए एक-दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दीं। पुलिसकर्मी हर त्योहार पर अपने परिवार से दूर रहकर सड़कों पर तैनात रहते हैं, ऐसे में यह आयोजन 'पुलिस परिवार' के आपसी भाईचारे और मानसिक तनाव को कम करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है।

2 दिन की धुलंडी के कारण बदला समय: धार्मिक मान्यताओं और चंद्र ग्रहण के प्रभाव के चलते इस बार धुलंडी का पर्व दो दिनों तक मनाया गया, जिसके कारण पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त समय तक सड़कों पर मुस्तैद रहना पड़ा।

जयपुर की 'ग्लोबल होली': खासा कोठी में 30 देशों के 4000 पर्यटकों ने उड़ाया गुलाल

राजस्थानी लोकनृत्यों और जायके के रंग में रंगे सात समंदर पार के मेहमान; पर्यटन विभाग के आयोजन ने मोहा मन

जयपुर (विशेष संवाददाता)। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस बार रंगों का पर्व 'धुलंडी' एक वैश्विक उत्सव के रूप में उभरकर सामने आया। चंद्र ग्रहण के विशेष प्रभाव के चलते प्रदेश में इस बार दो दिनों तक होली का उल्लास बना रहा। इसी क्रम में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक खासा कोठी होटल में 'होली फेस्टिवल 2026' का भव्य आयोजन किया गया। इस उत्सव में दुनिया के कोने-कोने से आए सैलानियों ने मरुधरा की सतरंगी संस्कृति का आनंद लिया और स्थानीय परंपराओं के प्रति अपना गहरा लगाव प्रदर्शित किया।

30 देशों के मेहमान और सुरक्षा के कड़े इंतजाम : पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि इस वर्ष खासा कोठी में आयोजित उत्सव में ईरान सहित करीब 25 से 30 देशों के लगभग 3500 से 4000 पर्यटक शामिल हुए। विभाग की ओर से विदेशी मेहमानों के लिए केमिकल-मुक्त प्राकृतिक गुलाल और विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं। पर्यटकों, विशेषकर महिला सैलानियों की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह मुस्तैद रहा और एडिशनल पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) राजीव पचार के नेतृत्व में चप्पे-चप्पे पर जाप्ता तैनात किया गया।

लोक धुनों पर थिरके विदेशी पांव : उत्सव के दौरान राजस्थानी लोक कलाकारों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। विदेशी सैलानी कालबेलिया, मयूर नृत्य, कच्ची घोड़ी और लंगा मांगणियार कलाकारों की धुनों पर खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। राजस्थानी लोकगीतों के साथ-साथ डीजे पर बजते बॉलीवुड गानों ने माहौल को और अधिक उत्साहपूर्ण बना दिया। पर्यटकों ने एक-दूसरे को रंग लगाकर 'हैप्पी होली' की बधाई दी और जयपुर की बेमिसाल आवभगत की प्रशंसा की।

पारंपरिक जायके और आर्थिक मजबूती : होली के इस जश्न में खान-पान का विशेष आकर्षण रहा। विदेशी मेहमानों ने राजस्थान के पारंपरिक व्यंजनों, विशेषकर दाल के पकौड़े और ठंडाई का जमकर लुत्फ उठाया। उपेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार, ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों का उद्देश्य राजस्थानी संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि पर्यटन क्षेत्र स्थानीय रोजगार का बड़ा आधार है और एक पर्यटक के आने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 13 लोगों को रोजगार मिलता है।

होली के सफल आयोजन के बाद अब पर्यटन विभाग आगामी गणगौर उत्सव की तैयारियों में जुट गया है, जहाँ एक बार फिर विदेशी मेहमानों के बड़े जमावड़े की उम्मीद जताई जा रही है।

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फरमान : 1 जुलाई तक ठीक करें स्कूलों की जर्जर दीवारें, वरना लगेगा ताला

'मासूमों की सुरक्षा पर नो कॉम्प्रोमाइज'; प्री-प्राइमरी कक्षाएं केवल ग्राउंड फ्लोर पर चलाने के निर्देश

जयपुर (विधि संवाददाता)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों की जर्जर इमारतों को बच्चों के लिए 'डेथ ट्रैप' बताते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति महेन्द्र कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि स्कूल भवन सुरक्षित नहीं पाए गए, तो उन्हें 1 जुलाई 2026 से संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि बच्चों की जान की कीमत पर 'बजट की कमी' जैसा कोई भी बहाना स्वीकार्य नहीं होगा।

प्री-प्राइमरी के लिए 'ग्राउंड फ्लोर' अनिवार्य

छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अदालत ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट की मौखिक टिप्पणी के अनुसार:

केवल भूतल (त्रह्श्रह्वठ्ठस्त्र स्न्र्द्यश्रश्रह्): प्री-प्राइमरी के बच्चों की कक्षाएं अनिवार्य रूप से केवल ग्राउंड फ्लोर पर ही लगेंगी।

नो बेसमेंट, नो अपर फ्लोर: आपात स्थिति (जैसे आग या भूकंप) में बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए उन्हें न तो बेसमेंट में बिठाया जा सकेगा और न ही ऊपरी मंजिलों पर।

हाईकोर्ट की सुनवाई के मुख्य बिंदु: एक नज़र में

कागजी घोड़े 3700 में से केवल 5 स्कूलों पर काम शुरू : सुनवाई के दौरान जब मरम्मत और निर्माण के आंकड़े सामने आए, तो अदालत ने गहरी नाराजगी जताई। विभाग के दावों की पोल खोलते हुए यह तथ्य सामने आया कि:

लक्ष्य: प्रदेश में कुल 3700 स्कूलों के नए भवन बनने थे।

हकीकत: अब तक केवल 114 स्कूलों को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।

धरातल पर स्थिति

महज 5 भवनों का काम ही प्लिन्थ लेवल तक पहुंच पाया है। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मार्च में बजट लैप्स होने की कगार पर है और विभाग अभी तक केवल टेंडर की फाइलों में उलझा हुआ है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि क्यों न निजी चार्टर्ड इंजीनियरों को जांच का जिम्मा दिया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

प्रवासियों की मदद और केंद्र का पक्ष

राज्य सरकार ने बताया कि स्कूल भवनों के पुनरुद्धार के लिए प्रवासियों से भी मदद ली जा रही है, जिसके माध्यम से अब तक 11 करोड़ रुपये का सहयोग जुटाया गया है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि राज्य की ओर से मांगे गए अतिरिक्त बजट के संबंध में अभी तक अधिकारियों से पूर्ण और स्पष्ट डेटा साझा नहीं किया गया है।

हाईकोर्ट के इस आदेश ने शिक्षा विभाग और निजी स्कूल संचालकों के बीच हड़कंप मचा दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन 1 जुलाई से पहले इन जर्जर दीवारों को दुरुस्त कर पाता है या नहीं।

चैत्र नवरात्रि 2026: 19 मार्च से शुरू होगा शक्ति की उपासना का महापर्व, नोट करें घटस्थापना का सबसे सटीक मुहूर्त

पालकी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा, हाथी पर होगी विदाई, इसी दिन से होगा हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) का आगाज़

जयपुर (विशेष संवाददाता)। होली के उल्लास के बाद अब भक्तों की नजरें चैत्र नवरात्रि पर टिकी हैं। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च, गुरुवार से होने जा रहा है।

यह दिन भारतीय संस्कृति के लिए दोहरे उत्सव का है, क्योंकि इसी पावन तिथि से हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) का भी आरंभ होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होने वाला यह पर्व नौ दिनों तक श्रद्धा और भक्ति का केंद्र रहेगा।

घटस्थापना: इस बार दो श्रेष्ठ मुहूर्त: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि के पहले दिन 'घटस्थापना' या कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार, सही मुहूर्त में की गई स्थापना ही पूर्ण फलदायी मानी जाती है। हालांकि प्रतिपदा तिथि 18 मार्च की रात से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन उदय तिथि की मान्यता के कारण घटस्थापना 19 मार्च को ही की जाएगी।

चैत्र नवरात्रि 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त

मां दुर्गा की सवारी आगमन और विदाई के संकेत ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवरात्रि में मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान विशेष संदेश लेकर आता है।

आगमन (पालकी पर): चूंकि इस साल नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रही है, इसलिए देवी मां पालकी (डोली) पर सवार होकर आएंगी।

ज्योतिषीय दृष्टि से यह शुभता के साथ-साथ भक्तों को धैर्य और संयम बरतने का संकेत देता है।

विदाई (हाथी पर): माता की विदाई हाथी पर होगी। इसे शास्त्रों में सुख-समृद्धि, खुशहाली और अच्छी वर्षा का प्रतीक माना जाता है।

क्या है घटस्थापना का महत्व ?

घटस्थापना का अर्थ है ब्रह्मांड की शक्ति का अपने घर में आह्वान करना। कलश को साक्षात देव स्वरूप माना जाता है, जिसमें सभी तीर्थों और देवी-देवताओं का वास होता है। ज्योतिषियों का कहना है कि यदि भक्त सुबह के समय स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो वे दोपहर के 'अभिजीत मुहूर्त' में कलश स्थापित कर सकते हैं, जिसे सबसे उत्तम और दोषमुक्त माना जाता है। नौ दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक, देवी के नौ रूपों की विधि-विधान से पूजा की जाएगी।

राजस्थान में बेटियों के लिए 'लाडो प्रोत्साहन योजना' जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक मिलेंगे ?1.5 लाख

बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सात किस्तों में मिलेगी आर्थिक मदद, राजश्री योजना का भी हुआ विलय

जयपुर (विशेष संवाददाता)। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की बेटियों को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाने के संकल्प के साथ 'लाडो प्रोत्साहन योजना' को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से राज्य सरकार एक बालिका के जन्म से लेकर उसके स्नातक (ग्रेजुएशन) पूरा करने तक कुल 1,50,000 रुपये की बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यह पहल न केवल बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर को सुधारेगी, बल्कि प्रदेश में लिंगानुपात और महिला साक्षरता की स्थिति को भी नई मजबूती प्रदान करेगी।

आवेदन की सरल प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

अभिभावकों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को काफी हद तक डिजिटल और सरल बनाया गया है। महिला के गर्भवती होने के समय एएनसी जांच के दौरान ही 'जन-आधार कार्ड' और बैंक खाते का विवरण अस्पताल में दर्ज कराना होता है। जन्म के समय अस्पताल प्रशासन द्वारा एक यूनिक पीसीटीएसआईडी जारी की जाती है, जो भविष्य की सभी किस्तों को ट्रैक करने के लिए अनिवार्य है। शुरुआती दो किस्तों के लिए किसी अलग फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती, जबकि स्कूली शिक्षा के दौरान 'ओजस' पोर्टल के माध्यम से डेटा अपडेट किया जाता है। अंतिम 1 लाख की किस्त के लिए छात्रा को 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर स्नातक की मार्कशीट उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो अभिभावक पहले से 'राजश्री योजना' का लाभ ले रहे थे, उन्हें किसी भी प्रकार के असमंजस में रहने की आवश्यकता नहीं है।

योजना की पात्रता और अनिवार्य शर्तें : लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने कुछ बुनियादी मापदंड तय किए हैं। योजना का प्राथमिक लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जहाँ बेटी की मां (प्रसूता) राजस्थान की स्थायी मूल निवासी है। इसके अतिरिक्त, यह अनिवार्य है कि बेटी का जन्म किसी राजकीय चिकित्सालय या जननी सुरक्षा योजना के तहत अधिकृत निजी अस्पताल में हुआ हो। सरकार ने एक उदार निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि यह लाभ तीसरी या उसके बाद की संतान (बेटी) होने पर भी समान रूप से देय होगा, जिससे अधिक से अधिक परिवार इस सुरक्षा चक्र से जुड़ सकें।

सात किस्तों का गणित कब और कितना मिलेगा पैसा ? : योजना के तहत मिलने वाली 1.5 लाख की कुल राशि सात महत्वपूर्ण पड़ावों पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

राजस्थान में रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुसीबत: 14 अप्रैल से 60 से अधिक ट्रेनें प्रभावित

चूरू-सादुलपुर रूट पर डबल लाइन और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम शुरू, 14 ट्रेनें रद्द, 29 के रूट बदले

बीकानेर/चूरू (विशेष संवाददाता)। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के अंतर्गत आने वाले चूरू-सादुलपुर रेल खंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। रेलवे द्वारा इस सेक्शन पर डबल लाइन डालने और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ब्लॉक अपग्रेडेशन का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस कारण 14 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 60 से अधिक ट्रेनें

प्रभावित रहेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी (सीपीआरओ) अमित सुदर्शन के अनुसार, सुरक्षा और तकनीकी विकास के लिए यह ब्लॉक अनिवार्य है।

ट्रेनों का गणित

17 दिन रहेगी हलचल रेलवे के अनुसार, 14 से 30 अप्रैल के बीच कुल प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है: आंशिक रूप से रद्द (शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट) 22 ट्रेनें मार्ग परिवर्तित 29 ट्रेनें रीशेड्यूल (समय में बदलाव) 02 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द ट्रेनें एक नज़र में प्रमुख ट्रेनों के रूट बदले: अब सीकर और जयपुर होकर चलेंगी

सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली, जयपुर और बीकानेर को जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों पर पड़ा है। कई ट्रेनें अब अपने नियमित मार्ग के बजाय सीकर-फतेहपुर या रिंगस-फुलेरा होकर चलेंगी लालगढ़-प्रयागराज (20404/03): 16-27 अप्रैल तक वाया चुरू-फतेहपुर-सीकर।

दिल्ली सराय-जोधपुर (22421/82)

15-28 अप्रैल तक वाया रेवाड़ी-रिंगस-फुलेरा-डेगाना। बीकानेर-हावड़ा/सियालदहः अप्रैल अंत में मेडता बाईपास-जयपुर-रेवाड़ी होकर चलेंगी। श्रीगंगानगर-बांद्रा टर्मिनस (14701) 25-27 अप्रैल तक वाया हनुमानगढ़-सूरतगढ़-बीकानेर-चुरू। रामेश्वरम-फिरोजपुर (20497) 14 व 21 अप्रैल को वाया रिंगस-रेवाड़ी-हिसार। वंदे भारत और जोधपुर-रेवाड़ी के समय में बदलाव यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना समय में बदलाव को लेकर है। बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत (26471) 16 से 25 अप्रैल तक बीकानेर से अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट देरी से रवाना होगी। जोधपुर-रेवाड़ी (14823) 15 अप्रैल को जोधपुर से अपने समय से 4 घंटे देरी से चलेगी। यात्रियों के लिए सलाहः रेलवे ने अपील की है कि यात्री घर से निकलने से पहले ऐप, 139 हेल्पलाइन या आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी ट्रेन की लाइव लोकेशन और स्टेटस जरूर चेक कर लें, ताकि स्टेशन पर होने वाली असुविधा से बचा जा सके।

स्वर्ण नगरी को बड़ी रेल सौगात : जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस का जैसलमेर तक अब होगा विस्तार

पर्यटन और व्यापार को मिलेंगे नए पंख, केंद्रीय मंत्री ने रेल मंत्री का जताया आभार

जैसलमेर (विशेष संवाददाता)। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर के लिए 5 मार्च का दिन खुशियों की नई सौगात लेकर आया। केंद्र सरकार ने क्षेत्रवासियों और पर्यटकों की वर्षों पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 20485/20486) का विस्तार अब 'स्वर्ण नगरी' जैसलमेर तक करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से न केवल स्थानीय यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि गुजरात और राजस्थान के बीच पर्यटन के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। कनेक्टिविटी से चमकेगा पर्यटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी साझा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का विशेष आभार व्यक्त किया। शेखावत ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'बेहतर कनेक्टिविटी' के विजन के तहत जैसलमेर को देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। यह ट्रेन विस्तार गुजरात से आने वाले हजारों सैलानियों के लिए 'लाइफलाइन' साबित होगा।'

व्यापार और स्थानीय आवाजाही को मिलेगी गति

वर्तमान में गुजरात से जैसलमेर आने वाले पर्यटकों को जोधपुर में ट्रेन बदलनी पड़ती थी या सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ता था।

व्यापारियों को लाभ

जैसलमेर के स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों को गुजरात के बाजारों तक पहुंचना आसान होगा।

सैलानियों के लिए सुगमता

साबरमती और अहमदाबाद क्षेत्र के पर्यटकों के लिए स्वर्ण नगरी की राह आसान हो जाएगी।

स्थानीय यात्री

जोधपुर और गुजरात के बीच सफर करने वाले स्थानीय लोगों को एक अतिरिक्त विश्वसनीय विकल्प मिलेगा। 'मील का पत्थर' साबित होगा यह निर्णय

शेखावत ने इस विस्तार को क्षेत्र की विकास यात्रा में एक 'मील का पत्थर' बताया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में बुनियादी ढांचे का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि, दोनों के लिए आवश्यक है। रेलवे के इस कदम से जैसलमेर के होटल उद्योग और गाइड व्यवसाय को भी बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए रेलवे और जेसीटीएसएल के बीच समन्वय को भी और बेहतर किया जा रहा है।

स्थानीय निवासियों और पर्यटन व्यवसायियों ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए इसे जैसलमेर के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है।

स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्रवेश का 'बिगुल'

आज से शुरू हुए आवेदन, जानें डेडलाइन, पात्रता और नियम

कक्षा 1 से 9 तक के लिए 16 मार्च तक लिए जाएंगे आवेदन, पहली कक्षा के लिए आयु सीमा और सीटें तय

जयपुर (विशेष संवाददाता)। राजस्थान के अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने उत्कृष्ट शिक्षा के लिए पहचाने जाने वाले स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र (2026-27) के लिए प्रवेश प्रक्रिया का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। 6 मार्च 2026 से इन स्कूलों में आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभिभावकों निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बच्चों का पंजीकरण सुनिश्चित करें।

16 मार्च तक का समय, देरी पड़ सकती है भारी : प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। स्कूल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया मुख्य रूप से कक्षा 1 से 9 तक के लिए है, जिसमें रिक्त सीटों के आधार पर दाखिला दिया जाएगा।

कक्षा 1 के लिए कड़े मापदंड

छोटे बच्चों के दाखिले के लिए शिक्षा विभाग ने आयु और सीटों की संख्या को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

आयु सीमा: 31 मार्च 2026 तक बच्चे की उम्र 6 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम होनी चाहिए।

सीटों की संख्या: कक्षा 1 में प्रवेश के लिए अधिकतम 40 सीटें ही उपलब्ध होंगी।

कक्षावार प्रवेश के नियम

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए अलग-अलग मानक तय किए गए हैं: कक्षा 2 से 8 तक: इन कक्षाओं में सीधे प्रवेश नहीं मिलेगा। पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों के बाद जो सीटें खाली रहेंगी, उन पर विभाग की 'प्रायोरिटी लिस्ट' के आधार पर दाखिला होगा।

कक्षा 9: इस कक्षा में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी। परीक्षा के बाद तैयार होने वाली मेरिट लिस्ट के आधार पर ही अंतिम चयन किया जाएगा।

कक्षा 10 और 12: बोर्ड कक्षाओं में प्रवेश पूरी तरह से सीबीएसई की गाइडलाइन्स और नियमों के अनुसार होगा।

आवश्यक दस्तावेज

अभिभावकों को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज स्कूल में जमा करने होंगे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।

आधार कार्ड

पिछली कक्षा की मार्कशीट (कक्षा 2 और उससे ऊपर के लिए)। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे आवेदन पत्र भरने से पहले संबंधित विद्यालय के सूचना पट्ट पर दी गई विस्तृत जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

हाड़ौती के विकास को लगे पंख : 6691 करोड़ की तीन बड़ी सौगातों से बदलेगी संभाग की तस्वीर

जल जीवन मिशनः नौनेरा और परवन अकावद परियोजनाओं से खत्म होगी पेयजल की पुरानी समस्या

हाड़ौती के 2.65 लाख से अधिक परिवारों के घरों में पहुंचेगा 'हर घर जल'

कोटा (विशेष संवाददाता)। राजस्थान के हाड़ौती संभाग (कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़) के निवासियों के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी है। इस पूरे क्षेत्र में विकास की रफ्तार को नई उड़ान देने और पेयजल के वर्षों पुराने संकट को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने कुल 6691.30 करोड़ रुपये की तीन ऐतिहासिक सौगातें दी हैं। इन महात्वाकांक्षी परियोजनाओं में बहुप्रतीक्षित नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के साथ-साथ 'जल जीवन मिशन' के तहत दो बड़ी पेयजल परियोजनाओं पर युद्धस्तर पर काम शुरू होने जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से हाड़ौती के हजारों गांवों की प्यास बुझेगी और लाखों परिवारों के घरों तक मीठा पानी पहुंचेगा।

लाभार्थी : कोटा और बूंदी जिलों के 749 गांव और 6 कस्बे।

फायदा: 1 लाख 13 हजार 287 परिवारों को मिलेगा 'हर घर जल'।

प्रगति: इस परियोजना को चार कार्यकारी पैकेजों में बांटा गया है। इसके पहले पैकेज (207.38 करोड़ रुपये) का कार्यादेश 4 दिसंबर 2025 को जारी किया जा चुका है। इसके तहत कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र सहित लाडपुरा, पीपल्दा, सांगोद और केशवरायपाटन में इन्टेक वेल, रॉ-वॉटर राइजिंग मैन और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा। हाड़ौती के विकास की तीसरी और सबसे बड़ी कड़ी 'परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना' है। सरकार ने इसके लिए 3523.16 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की है।

कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट (1507 करोड़ रुपये)

इन तीन बड़ी सौगातों में सबसे प्रमुख नया कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसका निर्माण 1507 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से किया जाएगा। इस एयरपोर्ट के बनने से हाड़ौती क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल स्थानीय व्यापार और उद्योगों को संजीवनी मिलेगी, बल्कि शिक्षा नगरी कोटा और आस-पास के पर्यटन स्थलों में भी विकास के नए रास्ते खुलेंगे। पेयजल संकट को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 1661.14 करोड़ रुपये की 'नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना' को मंजूरी दी गई है।

बारां में टूटा 128 साल का इतिहासः इस साल नहीं निकलेगी गणगौर की शाही शोभायात्रा

प्रशासन की बेरुखी और बजट के अभाव ने फेरा खुशियों पर पानी, गणगौर सेवा समिति ने भारी मन से लिया फैसला

बारां (विशेष संवाददाता)। राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान और लोक आस्था के प्रतीक 'गणगौर' पर्व को लेकर बारां शहर से एक मायूस करने वाली खबर है। पिछले 128 वर्षों से अनवरत चली आ रही गणगौर की शाही शोभायात्रा की परंपरा इस बार टूट गई है। नगर परिषद की ओर से अनुदान राशि न मिलने और बढ़ती महंगाई के कारण 'गणगौर सेवा समिति' ने इस वर्ष शोभायात्रा न निकालने का निर्णय लिया है। इस फैसले से उन हजारों महिलाओं और श्रद्धालुओं में भारी निराशा है, जो साल भर इस ऐतिहासिक सवारी का इंतजार करते हैं।

क्यों थम गई 'शाही सवारी'?

शोभायात्रा को लेकर हाल ही में दिनेश गौतम की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा और संरक्षक ललित मोहन खंडेलवाल ने बताया कि इस भव्य आयोजन को संपन्न कराने में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये का खर्च आता है।

अनुदान का अभाव: समिति के अनुसार, यह आयोजन जनसहयोग और मुख्य रूप से नगर परिषद के आर्थिक अनुदान पर निर्भर रहता था। लेकिन इस बार नगर परिषद द्वारा सहयोग न मिलने के कारण समिति आर्थिक संकट में है।

महंगाई की मार: टेंट, बैंड-बाजे, सजावट और सुरक्षा व्यवस्थाओं के बढ़ते खर्चों के बीच बिना सरकारी मदद के इतना बड़ा आयोजन करना समिति के लिए संभव नहीं रहा। बैठक के दौरान समिति सदस्य रामभरोस सेन, बुद्धिप्रकाश जोशी, मनोज शर्मा, विनोद पंडित, महेश सोनी, ललित शर्मा लाला, गोविंद सोनी और आयुष पार्षद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

सभी ने एक स्वर में नगर परिषद के असहयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक शताब्दी से अधिक पुरानी परंपरा का इस तरह समाप्त होना शहर की सांस्कृतिक क्षति है।

धार्मिक महत्व : 16 दिनों की कठिन तपस्या का फल

इस वर्ष गणगौर का पावन पर्व 21 मार्च को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार, यह पर्व प्रेम और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 16 दिनों तक निराहार रहकर कठोर तपस्या की थी। इसी तपस्या के सम्मान में यह पर्व 16 दिनों तक चलता है और पूजा में 16 शृंगार व 16 की संख्या में ही सामग्री चढ़ाई जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए ईसर-गणगौर की विशेष पूजा-अर्चना करती हैं। बारां में शोभायात्रा रद्द होने से भले ही सड़कों पर रौनक कम रहे, लेकिन श्रद्धालु अपने घरों में परंपरा के अनुसार पूजन कर माता गणगौर से खुशहाली की कामना करेंगे।

दस्तावेजों में ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद 'एसपीएस ट्रैश हैंडलर्स' को थमाया ठेका | प्रतिबंधित फर्म पर मेहरबानी, मंत्री के जांच आदेश भी किए दरकिनार

कोटा नगर निगम में 123 करोड़ का 'सफाई घोटाला'

झूठा शपथ पत्र देकर निगम के अफसरों के साथ मिलकर रचा 'बड़ा खेल'

कोटा (विशेष संवाददाता)। कोटा दक्षिण नगर निगम में 'स्मार्ट सफाई' की आड़ में ?123 करोड़ के भारी-भरकम भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। नियमों को ताक पर रखकर निगम के आला अधिकारियों ने एक ऐसी फर्म को सफाई का जिम्मा सौंप दिया, जो सरकारी तौर पर प्रतिबंधित है।

चौंकाने वाली बात यह है कि इस खेल में न केवल दस्तावेजों की अनदेखी की गई, बल्कि स्वायत्त शासन (यूडीएच) मंत्री के जांच के आदेशों को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। झूठे शपथ पत्र से मिला

करोड़ों का काम विवादों के घेरे में आई जॉइंट वेंचर फर्म 'स्क्र ट्रैश हैंडलर्स' की लीड पार्टनर 'मैसर्स सुखपाल सिंह कंस्ट्रक्शन' है। नियमानुसार, किसी भी टेंडर में भाग लेने के लिए फर्म का बेदाग होना अनिवार्य है।

झालावाड़ से थी प्रतिबंधित

झालावाड़ नगर परिषद ने 19 अक्टूबर 2023 को इस फर्म को तीन साल के लिए डीबार किया था।

छिपाई जानकारी

फर्म ने टेंडर के दौरान निगम में झूठा शपथ पत्र पेश किया कि वह कहीं भी डीबार नहीं है। जबकि निगम के चीफ इंजीनियर के पास इसके ब्लैकलिस्ट होने की लिखित सूचना (पत्र क्रमांक 7771-74) पहले से मौजूद थी।

मंत्री के आदेश को दी चुनौती

इस टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत 9 मई 2025 को राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा तक पहुंची थी। मंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 मई 2025 को निदेशक को जांच के कड़े निर्देश दिए थे। लेकिन निगम के अफसरों ने जांच पूरी होने का इंतजार करने के बजाय, महज 11 दिन बाद 26 मई को आनन-फानन में फर्म को अंतिम स्वीकृति जारी कर दी।

नियमों को मरोड़ा चहेतों के लिए बदली गईं शर्तें

सफाई के इस 'स्मार्ट' खेल में नियमों को मोम की तरह मरोड़ा गया। टेंडर की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाया गया और 14 महत्वपूर्ण शर्तों में फेरबदल किया गया।

सबसे गंभीर आरोप यह है कि निगम ने अपने खर्चे पर 28 करोड़ खर्च करके 210 नए कचरा टीपर खरीदे और बिना किसी ठोस आधार के ठेकेदार कंपनी को इस्तेमाल के लिए सौंप दिए।

किसका क्या है कहना?

'फर्म अगर डीबार है तो वह इस तथ्य को छुपा नहीं सकती। शपथ पत्र में इसका जिक्र करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।'

— अनिल अग्रवाल, संभागीय आयुक्त एवं प्रशासक, नगर निगम

'हमने इस फर्म को 2023 में ही तीन साल के लिए डीबार कर दिया था। इसकी आधिकारिक सूचना कोटा निगम को समय पर भेज दी गई थी।'

— अशोक शर्मा, आयुक्त, नगर परिषद झालावाड़

'हमारी फर्म झालावाड़ के अलावा अन्य कहीं भी टेंडर ले सकती है। हमने कोई जानकारी नहीं छिपाई है और न ही शपथ पत्र झूठा है।'

— जतिनपाल सिंह, डायरेक्टर, मैसर्स सुखपाल सिंह कंस्ट्रक्शन

सम्पादकीय

अमेरिका का मुगालता रूस से तेल खरीद की छूट उदारता नहीं मजबूरी

अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारत को रूस से एक माह तक तेल खरीदने की छूट को लेख मजबूरी बताता है, उदारता नहीं। भारत ने यूरोपीय संघ से व्यापार समझौता कर अमेरिका को संदेश दिया कि उसके पास अन्य विकल्प हैं।

अमेरिकी प्रशासन ने भारत को रूस से एक माह तक तेल खरीदने की जो कथित छूट दी, उससे कुछ ऐसा ध्वनित हो रहा है कि यह तय करने का अधिकार उसने अपने हाथ ले लिया है कि कौन देश किससे, कब तेल खरीद सकता है और कौन नहीं? उसके पास ऐसा कोई अधिकार न था, न है और न हो सकता है, लेकिन यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के बहाने वह लंबे समय से भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाए हुए है।

उसने भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ भी थोपा, पर भारत ने इसकी परवाह नहीं की। आखिरकार उसने अपने स्तर से ही भारत से अंतरिम व्यापार समझौता पर सहमति बन जाने की घोषणा करते हुए पारस्परिक टैरिफ 25 से 18 प्रतिशत किया और रूस से तेल खरीदने के कारण लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को खत्म किया।

वास्तव में वह ऐसा करने के लिए बाध्य हुआ, क्योंकि भारत ने यूरोपीय संघ से सभी व्यापार समझौते की जननी कहे जाने वाला व्यापार समझौता कर उसे यह संदेश दिया कि उसके पास और भी विकल्प हैं। सच यह भी है कि भारत ने रूस से तेल खरीद पूरी तौर पर कभी भी बंद नहीं की। जनवरी और फरवरी माह में भी उसने रूस से तेल खरीदा। इसके अलावा भारत बार-बार यह भी दोहराता रहा है कि वह अपने ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए रूस समेत कहीं से भी तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है।

आखिर जब भारत रूस से तेल खरीद ही रहा है तो फिर अमेरिका के यह कहने का क्या मतलब कि वह भारत को उससे 30 दिन के लिए तेल खरीदने की छूट दे रहा है? अमेरिका ने तथाकथित उदारता दिखाते हुए भारत को रूस से तेल खरीदने की जो मंजूरी दी, वह उसकी मजबूरी का ही परिचायक है। वह जानता है कि ईरान से युद्ध के कारण पश्चिम एशिया से तेल एवं गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है और उनके दाम भी बढ़ रहे हैं।

इससे समूची विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष जो संकट पैदा होगा, उसके दुष्प्रभाव से वह भी नहीं बच पाएगा। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तेल एवं गैस की आपूर्ति का जो वैश्विक संकट खड़ा हो गया है, उसके लिए मूलत: अमेरिका ही जिम्मेदार है। यदि वह इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला नहीं करता तो होर्मुज जल मार्ग से तेल की आपूर्ति बाधित नहीं होती।

यह अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वह उक्त जल मार्ग से पश्चिम एशियाई देशों से आने वाले तेल की आपूर्ति की बाधाओं को दूर करे, लेकिन फिलहाल वह इसमें समर्थ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान हार मारने को तैयार नहीं। अच्छा हो कि अमेरिका इस मुगालते से बाहर आए कि वह हर मामले में न तो अपनी ही चला सकता है और न ही अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा व्यापार पर एकाधिकार कर सकता है। उसे यह भी आभास हो जाए तो अच्छा कि ईरान वेनेजुएला नहीं है।

विचार-1

सुरों की हत्या और हमारी चुप्पी एक विचार और सुझाव

भारतीय शास्त्रीय संगीत और ध्रुवपद, जो कभी हमारी पहचान, आत्मा और साधना के प्रतीक थे, आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मंच सिमटते जा रहे हैं, श्रोता घटते जा रहे हैं, कलाकार आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक उपेक्षा से टूटते जा रहे हैं-और समाज, सत्ता तथा कॉरपोरेट जगत इस पूरी प्रक्रिया के मौन दर्शक बने हुए हैं।

■ सर्वेश भट्ट

शास्त्रीय संगीत और ध्रुवपद को बचाने के लिए क्या अब भी कोई जागेगा?

जब इतिहास आने वाले समय में हमारी सांस्कृतिक चेतना का मूल्यांकन करेगा, तो संभव है सबसे कठोर प्रश्न यही होगा- क्या हमने अपनी सबसे समृद्ध कला-परंपरा को मरते हुए चुपचाप देख लिया?

भारतीय शास्त्रीय संगीत और ध्रुवपद, जो कभी हमारी पहचान, आत्मा और साधना के प्रतीक थे, आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मंच सिमटते जा रहे हैं, श्रोता घटते जा रहे हैं, कलाकार आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक उपेक्षा से टूटते जा रहे हैं-और समाज, सत्ता तथा कॉरपोरेट जगत इस पूरी प्रक्रिया के मौन दर्शक बने हुए हैं। यह केवल उपेक्षा नहीं, सांस्कृतिक अपराध है।

जब मुनाफा संस्कृति से बड़ा हो जाए

आज कॉरपोरेट भारत मुनाफे, ब्रांड वैल्यू और वैश्विक विस्तार की नई-नई इबारतें लिख रहा है। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के नाम पर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में निवेश हो रहा है, लेकिन कला और संस्कृति जैसे अस्तित्वकारी विषय अब भी प्राथमिकताओं की सूची से बाहर हैं।

प्रश्न यह नहीं कि औद्योगिक घराने क्या कर रहे हैं, बल्कि यह है कि वे क्या नहीं कर रहे। क्या शास्त्रीय संगीत और ध्रुवपद उनके लिए केवल पोस्टर सजाने वाली विरासत भर हैं? क्या अरबों का लाभ कमाने वाले उद्योग अपनी सांस्कृतिक जड़ों के संरक्षण की ज़िम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं?

शास्त्रीय संगीत और ध्रुवपद में निवेश कोई अनुदान नहीं, यह सांस्कृतिक ऋण की अदायगी है। यदि यह ऋण नहीं चुकाया गया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी।

सांस्कृतिक केंद्र : आयोजन या औपचारिकता?

देशभर में बने भव्य सांस्कृतिक परिसर आज इवेंट मैनेजमेंट के अड्डे बनते जा रहे हैं। जयपुर का जवाहर कला केंद्र हो या अन्य प्रतिष्ठित संस्थान, क्या इनकी भूमिका केवल उत्सवों, समारोहों और सालाना कैलेंडर तक सीमित रहनी चाहिए?

शास्त्रीय संगीत और ध्रुवपद की आत्मा निरंतरता में बसती है, न कि चमकदार पोस्टरों और प्रायोजित समारोहों में। जब तक नियमित साप्ताहिक या पाक्षिक संगीत सभाएं नहीं होंगी, तब

तक श्रोता निर्माण और सांस्कृतिक संस्कार की बात केवल भाषण बनकर रह जाएगी।

क्या कारण है कि करोड़ों के बजट वाले संस्थान नियमित शास्त्रीय सभाएं नहीं कर सकते? क्या यह इच्छाशक्ति का अभाव नहीं है?

ध्रुवपद : जड़ों की निर्मम उपेक्षा

ध्रुवपद भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा है, उसकी जड़, उसका प्राण, उसका आधार है । पर विडंबना देखिए कि आज यही विधा सबसे अधिक हाशिये पर है।

ध्रुवपद साधक वर्षों की कठिन साधना के बाद भी सीमित मंच, सीमित आमंत्रण और सीमित सम्मान में सिमटकर रह जाते हैं। यह केवल एक कला-विधा की उपेक्षा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों से विमुखता का प्रमाण है। यदि ध्रुवपद की यह उपेक्षा जारी रही, तो शास्त्रीय संगीत केवल सतही प्रदर्शन बनकर रह जाएगा-आत्मा विहीन, खोखला और बाज़ार-निर्भर।

कुछ नाम, जो अब भी परंपरा को थामे हैं

इस अंधकार में भी कुछ दीपक जल रहे हैं ड्ड शास्त्रीय संगीत में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद अमजद अली खान, परवीन सुल्ताना, पंडित विश्वमोहन भट्ट, उस्ताद शुजात हुसैन, पं. अजय चक्रवर्ती, विदुषी कौशिकी चक्रवर्ती, सुनंदा शर्मा, उस्ताद मोईनुद्दीन खान, पंडित सलिल भट्ट, बंगश बंधु, मिश्र बंधु, पं. रोनू मजूमदार, पं. तरुण भट्टाचार्य,राहुल शर्मा, राकेश चौरसिया, डॉ. वर्षा अग्रवाल, नाबानिता चौधरी, पूर्वी मेहता, हेतल मेहता,पं. रवि शंकर भट्ट तैलंग, पं. आलोक भट्ट और युवा मोमिन खान जैसे कलाकार आज भी सुरों की मर्यादा बचाए हुए हैं।

ध्रुवपद परंपरा में उस्ताद वासिफुद्दीन डागर, विदुषी डॉ. मधु भट्ट तैलंग, उदय भवालकर, गुंडेचा बंधु, बहाउद्दीन डागर, नफीसुद्दीन अनिसुद्दीन डागर जैसी विभूतियां इस विधा को जीवनदान दे रही हैं।

कब तक चंद कंधे पूरी परंपरा का बोझ उठाते रहेंगे?

श्रोता निर्माण नहीं हुआ तो सब व्यर्थ

किसी भी कला का भविष्य श्रोताओं के बिना असंभव है। आज विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संगीत लगभग अनुपस्थित है। न संगीत सभाएँ, न संवाद, न जीवंत प्रस्तुतिड्ड परिणामस्वरूप एक पूरी पीढ़ी सुरों की संवेदना से वंचित होती जा रही है।

जब तक संगीत को संस्कार की तरह नहीं सिखाया जाएगा, तब तक शास्त्रीय संगीत और ध्रुवपद विशिष्ट वर्ग की बपौती बने रहेंगे-और धीरे-धीरे लुप्त होते चले जाएंगे।

अब नहीं चेते, तो इतिहास माफ नहीं करेगा

यह समय उत्सवों की आत्ममुग्धता छोड़कर ठोस सांस्कृतिक नीति बनाने का है। यह समय है कि कॉरपोरेट जगत, सरकार और सांस्कृतिक संस्थान मिलकर निर्णायक हस्तक्षेप करें। अन्यथा वह दिन दूर नहीं, जब भारतीय शास्त्रीय संगीत और ध्रुवपद केवल शोध-पत्रों, संग्रहालयों और स्मृति-ग्रंथों तक सीमित रह जाएंगे।

सवाल साफ है :

क्या हम सुरों की इस हत्या के साक्षी बनकर चुप बैठे रहेंगे, या समय रहते अपनी सांस्कृतिक आत्मा को बचाने के लिए खड़े भी होंगे?

(कला समीक्षक, मुंबई)

स्टार्टअप्स : संभावनाएं, चुनौतियां और समाधान!

■ हनुमंत सिंह

नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम केवल संख्या से नहीं, बल्कि सही सोच, समय पर सहयोग, तकनीकी मार्गदर्शन और संवेदनशील नीति से सफल होता है। यदि नवयुवा, फंडिंग एजेंसियां और नवाचार केंद्रों के संचालक सभी नवाचार की वास्तविक सोच के साथ आगे बढ़ें, तभी देश वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

पिछले अंक के लेख में नवाचार, नवप्रवर्तन और स्टार्टअप्स की भूमिका को देश की उन्नति और आत्मनिर्भरता से जोड़ते हुए यह बताया गया था कि कैसे भारत ने बीते वर्षों में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किया है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है की इतने प्रयासों, नीतियों और योजनाओं के बावजूद स्टार्टअप्स की सफलता में अत्यधिक देरी और असफलता की दर इतनी अधिक क्यों है?

फंडिंग और समय की चुनौती: स्टार्टअप असफलता का सबसे बड़ा और वास्तविक कारण फंड मिलने में अधिक समय या फंड न मिल पाना। भारत में विश्व का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम होने का अर्थ यह भी है कि यहां नवाचार और स्टार्टअप्स की संख्या अत्यधिक है। परंतु इन बड़ी संख्याओं के अनुपात में मेंटोरशिप, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहयोग उपलब्ध नहीं है। अक्सर यह देखा जाता है कि किसी स्टार्टअप को पहले तो फंड स्वीकृति मिलने में ही लंबा समय लग जाता है, और यदि स्वीकृति मिल भी जाए, तो फंड जारी होने में वर्षों लग जाते हैं। प्रश्न यह है कि कोई नवयुवा अपने विचार को कितने वर्षों तक केवल प्रतीक्षा में रख सकता है?

यह स्थिति केवल बड़े स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन जैसे मंचों पर भी, जहाँ देश भर के स्कूली छात्र नवाचार प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चयनित शीर्ष छात्रों को भी कुछ सौ रुपये की प्रोत्साहन राशि वर्षों तक नहीं मिल पाती। इससे नवाचार के प्रति उत्साह स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है। सरकार ने नवाचार और स्टार्टअप्स को सहयोग देने के लिए देश भर में अनेक नवाचार केंद्र और इनक्यूबेशन हब स्थापित किए हैं। परंतु इन केंद्रों के संचालन में एक गंभीर समस्या दिखाई देती है। अधिकांश नवाचार केंद्रों का संचालन एसबीए विशेषज्ञों या औपचारिक सोच वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों के हाथों में है।

तकनीकी संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक और प्रोफेसर पहले से ही शिक्षण और प्रयोगशाला कार्यों के बोझ से दबे रहते हैं, इसलिए वे स्टार्टअप्स के मूल्यांकन में सीमित भूमिका ही निभा पाते हैं। परिणामस्वरूप, नवाचारों का मूल्यांकन ऐसे लोग करते हैं जो नवाचार की मूल भावना और उत्पाद-आधारित तकनीकी सोच से अनभिज्ञ होते हैं।

कई मामलों में स्टार्टअप्स के नवाचारों को सिरे से खारिज कर दिया जाता है, लेकिन यह बताने वाला कोई नहीं होता कि उस नवाचार को किस प्रकार सुधारा या विकसित किया जाए । जबकि सही मार्गदर्शन मिलने पर वही नवाचार एक मिसाल बन सकता था।

एक स्टार्टअप अपने विचार के साथ देश की आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुरूप समाधान प्रस्तुत करता है। लेकिन जब वह मेंटरशिप की तलाश में

जाता है, तो उसे अक्सर केवल मार्केटिंग और बिजनेस मॉडल से जुड़ी सलाह ही मिलती है।

आज बाजार में उपभोक्ताओं की दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए प्लेटफॉर्म बनाना और बड़े आंकड़े दिखाना नवाचार नहीं है। यह केवल एक व्यावसायिक मॉडल है, जो गिग वर्कर्स पैदा करता है। ऐसे प्लेटफॉर्म नवयुवाओं को अल्प वेतन पर रोजगार तो देते हैं, लेकिन तकनीकी दक्षता और दीर्घकालिक कौशल प्रदान नहीं करते।

यह विचार कि उपभोक्ता की जरूरत घर बैठे पूरी कर दी जाए, विकसित देशों में पहले से मौजूद है। इसकी नकल को नवाचार कहना और इसके लिए स्टार्टअप सुविधाओं-जैसे टैक्स छूट, आर्थिक सहायता और सामाजिक प्रतिष्ठा-का पूरा लाभ देना, वास्तविक नवाचारों के साथ अन्याय है।

असफलता की कीमत अकेला स्टार्टअप क्यों चुकाए?

एक आम धारणा यह है कि स्टार्टअप का हर विचार सफल ही होगा, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। नवाचार को साकार करने की यात्रा में अनेक बाधाएँ आती हैं। किसी भी तकनीकी नवाचार के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, फिजिक्स जैसी कई शाखाओं का ज्ञान आवश्यक होता है, जो एक अकेले स्टार्टअप के लिए संभव नहीं होता।

तकनीकी सहयोग और संसाधनों की कमी के कारण स्टार्टअप अपनी अवधारणा को साकार करने में देर कर देता है। इस दौरान विकसित देशों में उसी अवधारणा पर कार्य शुरू हो जाता है और भारतीय स्टार्टअप पीछे छूट जाता है।

सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि यदि कोई नवयुवा अपने जीवन के पाँच वर्ष पूरी निष्ठा से एक स्टार्टअप को देता है, नौकरी नहीं करता, और अंतत: फंड व सहयोग के अभाव में असफल हो जाता है-तो उसका भविष्य क्या होगा?

जब वह नौकरी के लिए आवेदन करता है, तो उससे पूछा जाता है कि डिग्री के बाद पाँच वर्षों तक उसने क्या किया। यह अंतराल उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बन जाता है। विडंबना यह है कि उसकी असफलता का मुख्य कारण सिस्टम की कमी होती है, लेकिन उसका दंड उसे अकेले ही भुगतना पड़ता है।

रिवर्स इंजीनियरिंग : अवसर या अपराध?

नवाचार को देश की परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में रिवर्स इंजीनियरिंग (उल्टा अभियांत्रीकरण) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से नवाचार और उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व हासिल किया।

भारत में भी अंतरिक्ष, रक्षा, सिविल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में रिवर्स इंजीनियरिंग का सफल उपयोग हुआ है। किंतु जब कोई नवयुवा इसी अवधारणा के साथ स्टार्टअप प्रस्तुत करता है, तो कई नवाचार केंद्रों में बैठे मूल्यांकनकर्ता इसे सिरे से खारिज कर देते हैं, क्योंकि वे नवाचार की व्यापक सोच से परिचित नहीं होते।

नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम केवल संख्या से नहीं, बल्कि सही सोच, समय पर सहयोग, तकनीकी मार्गदर्शन और संवेदनशील नीति से सफल होता है। यदि नवयुवा, फंडिंग एजेंसियां और नवाचार केंद्रों के संचालक सभी नवाचार की वास्तविक सोच के साथ आगे बढ़ें, तभी देश अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

अन्यथा यह पूरी प्रक्रिया केवल एक भ्रामक व्यवस्था बनकर रह जाएगी, जिसमें साहसी नवयुवाओं के सपने और देश की संभावनाएं दोनों ही खो जाएंगी।

(लेखक प्रख्यात शोधकर्ता हैं)

जेडीए सीमा विस्तार का 'साइड इफेक्ट'

ग्रामीण इलाकों में अवैध कॉलोनियों की बाढ़, विधानसभा में गूंजा मुद्दा

जयपुर (विधानसभा संवाददाता)। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के कार्यक्षेत्र विस्तार और इसके चलते ग्रामीण इलाकों में पनप रहे अवैध निर्माण का मुद्दा गरमाया रहा। कांग्रेस विधायक शिखा मिलन ने सदन में शून्यकाल के दौरान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए जेडीए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए।

विधायक शिखा मिलन ने आरोप लगाया कि जब से जेडीए की सीमाओं का विस्तार हुआ है, तब से ग्रामीण क्षेत्रों में भू-माफिया सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर के बाहरी और ग्रामीण इलाकों में बिना किसी वैधानिक स्वीकृति और मास्टर प्लान के नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से कॉलोनियां काटी जा रही हैं।

भविष्य का संकट: विधायक ने चेतावनी दी कि बिना अनुमति विकसित हो रही ये कॉलोनियां भविष्य में वहां रहने वाले लोगों के

लिए बुनियादी सुविधाओं (सड़क, पानी, बिजली) का बड़ा संकट पैदा करेंगी।

नियमों की अनदेखी: बिना किसी तकनीकी जांच या ले-आउट अप्रूवल के जमीन की बंदरबांट की जा रही है।

जलभराव वाले क्षेत्रों में भी निर्माण, सुरक्षा पर खतरा : सदन में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह पेश किया गया कि कई स्थानों पर उन क्षेत्रों में भी अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, जहाँ बारिश के समय जलभराव की समस्या रहती है।

सुरक्षा से समझौता: शिखा मिलन ने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों में निर्माण होने से न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि भविष्य में मानसून के दौरान वहां गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

जेडीए की 'चुप्पी' पर उठाए सवाल

विधायक ने जेडीए प्रशासन पर मिलीभगत और अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हो और प्रशासन को इसकी भनक न हो। उन्होंने मांग की कि जेडीए प्रशासन को इन अवैध कॉलोनियों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भविष्य में अव्यवस्थित शहरीकरण को रोकने के लिए प्रभावी अंकुश लगाया जाए। अवैध कॉलोनियों के निर्माण को शुरुआती स्तर पर ही ध्वस्त किया जाए।

मनरेगा भुगतान पर विधानसभा में बहस

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बोले- 'केंद्र से बजट मिलते ही मजदूरों को मिलेगी मजदूरी'

जयपुर (विधानसभा संवाददाता)। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सोमवार को मनरेगा मजदूरों के लंबित भुगतान और कार्यों की स्वीकृति का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा? जालोर जिले में श्रमिकों को समय पर मजदूरी न मिलने के संबंध में पूछे गए सवाल पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट किया कि भुगतान में हो रही देरी का मुख्य कारण केंद्र सरकार से राशि मिलने में हो रहा विलंब है?

प्रश्नकाल के दौरान जालोर से विधायक समरजीत सिंह ने सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि जिले में मनरेगा के कार्य तो स्वीकृत हो रहे हैं, लेकिन मजदूरों को उनकी मेहनत का पैसा समय पर नहीं मिल पा रहा है? उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि अधिकांश कार्यों की स्वीकृति राज्य स्तर (जयपुर) से दी जा रही है, जिससे प्रक्रिया जटिल हो गई है और देरी हो रही है?

विधायक के आरोपों का खंडन करते हुए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट किया कि मनरेगा कार्यों की फाइलें राज्य स्तर पर नहीं मंगाई जाती हैं? उन्होंने सदन को बताया कि कार्यों की स्वीकृति के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू है और यह अधिकार पूरी तरह से जिला स्तर पर ही सुरक्षित है?

भुगतान में देरी की दो बड़ी वजहें : बहस के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर सवाल किया, तो मंत्री ने देरी के लिए दो प्रमुख तकनीकी कारणों को जिम्मेदार ठहराया।

केंद्रीय अंशदान में विलंब

भुगतान में देरी का प्राथमिक कारण केंद्र सरकार के हिस्से की राशि समय पर प्राप्त न होना है। इसके लिए भारत सरकार को पहले ही औपचारिक पत्र लिखा जा चुका है?

दस्तावेजों की अपूर्णता

कई मामलों में श्रमिकों की ओर से केवाईसी या अन्य आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति समय पर नहीं हो पाती, जिससे तकनीकी स्तर पर भुगतान प्रक्रिया अटक जाती है?

मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि जैसे ही केंद्र से बजट प्राप्त होगा, सभी लंबित भुगतान प्राथमिकता के आधार पर मजदूरों के खातों में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे?

विधानसभा में गूंजा टी-20 वर्ल्ड कप का जश्न : जूली का तंज 'मोदी मैच देखने नहीं गए, इसलिए टीम इंडिया जीत गई'

जयपुर (विधानसभा संवाददाता)। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम की टी-20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत की गूंज सुनाई दी। शून्यकाल के दौरान जहाँ सत्ता पक्ष ने इस जीत को 'नरेंद्र मोदी स्टेडियम' और नए भारत के गौरव से जोड़ा, वहीं विपक्ष ने स्टेडियम के नामकरण और प्रधानमंत्री की उपस्थिति को लेकर तीखे कटाक्ष किए।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में टीम इंडिया को बधाई देते हुए इस जीत को यादगार बताया। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिस पर हर नागरिक को गर्व है। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने विपक्षी खेमे पर निशाना साधते हुए कहा, 'हमने न केवल वर्ल्ड कप जीता है, बल्कि टीम ने तीन रिकॉर्ड भी बनाए हैं। आईसीसी

वर्ल्ड कप को तीन बार जीतना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने स्टेडियम के नाम का बचाव करते हुए कहा कि उसका नाम 'टीकाराम जूली स्टेडियम' तो रख नहीं सकते थे।

'पिछली बार आपने हरवा दिया था' - नेता प्रतिपक्ष का पलटवार

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्टेडियम के नामकरण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसका नाम पहले 'सरदार पटेल स्टेडियम' था, जिसे बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। उन्होंने जीत की बधाई देने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि 'टीम इंडिया की जीत की बधाई सब देते हैं, लेकिन पिछली बार आपने हरवा दिया था। मोदीजी जब-जब मैच देखने गए, टीम हार गई थी। कल मोदीजी मैच देखने नहीं गए, इसलिए टीम जीत गई'।

सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार-पलटवार

जूली के इस बयान के बाद सदन में काफी देर तक शोर-शराबा और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक चलती रही। कांग्रेस विधायकों ने जूली की बात का समर्थन किया, वहीं भाजपा मंत्रियों ने इसे खेल भावना के विपरीत और राजनीति से प्रेरित बयान बताया।

शिक्षामंत्री और नेता प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक प्रदेश में 840 खेल कोचों की होगी भर्ती

विधानसभा में गूंजा 'भांग' विवाद

जयपुर (विधानसभा संवाददाता)। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान जबरदस्त हंगामा और सियासी बयानबाजी देखने को मिली। जहाँ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के 'भांग' वाले बयान ने सदन में उबाल ला दिया, वहीं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ी भर्ती की घोषणा कर राहत दी।

डोटासरा ने भांग खाकर खोले स्कूल : सदन में अंग्रेजी मीडियम और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में रिक्त पदों का मुद्दा उस समय गरमा गया जब बीजेपी विधायक बालकनाथ ने इस पर सवाल पूछा। जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने

बिना किसी पद सृजन के 3737 स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में बदल दिया।

दिलावर ने कहा कि कई स्कूलों में केवल 1 से 10 बच्चे ही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 'भांग खाकर' ये स्कूल खोल दिए थे।

इस टिप्पणी पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी आपत्ति जताई।

उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री का जवाब मर्यादित नहीं है और ऐसा लगता है जैसे वे खुद भांग खाकर जवाब दे रहे हों।

खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात

खेल विभाग में वर्षों से चल रही कोच की कमी को दूर करने के लिए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सदन में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने निर्दलीय विधायक यूनुस खान के सवाल के जवाब में कहा कि 2012 के बाद पहली बार बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।

140 स्थायी पद

वित्त विभाग ने 140 स्थायी कोचों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) इस दिशा में आगे की कार्यवाही कर रहा है।

700 अस्थायी पद

विभाग 700 अस्थायी (टेंपरेरी) कोच भी नियुक्त करेगा ताकि प्रदेश के हर खेल प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षक उपलब्ध हो सकें।

राजस्थान की नारी 'Resilience, Result और Revolution' की प्रतीक : राज्यवर्धन राठौड़

जयपुर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 'महिला सम्मान समारोह एवं परिचर्चा' आयोजित, उद्योग मंत्री ने महिला उद्यमियों को किया सम्मानित

जयपुर (विशेष संवाददाता)। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान की नारी अब केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह 'Resilience (लचीलापन), Result (परिणाम) और Revolution (क्रांति)' का जीवंत प्रतीक बन चुकी है। रविवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित 'महिला सम्मान समारोह एवं परिचर्चा' को संबोधित करते हुए उन्होंने यह विचार व्यक्त किए।

पीएम मोदी के विजन से सामाजिक बदलाव कर्नल राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना ने देश में गहरी सामाजिक जागरूकता पैदा की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्ष 2014 के बाद से महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई और सार्थक चर्चा शुरू हुई है, जिसका परिणाम आज खेल, उद्योग और प्रशासन जैसे हर क्षेत्र में महिलाओं के बेहतरीन प्रदर्शन के रूप में सामने आ रहा है।

विकसित भारत-2047 में महिलाओं की भूमिका मंत्री ने कहा कि 'विकसित भारत-

2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांवों और कस्बों की लघु महिला उद्यमियों का योगदान निर्णायक होगा। उन्होंने सफल उद्यमियों से आह्वान किया कि वे अन्य महिलाओं को भी सरकार की सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाओं से जोड़ें, ताकि जमीनी स्तर पर एक बड़ी आर्थिक क्रांति लाई जा सके। सम्मान और योजनाओं का लाभ वितरण समारोह के दौरान कर्नल राठौड़ ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 11 महिलाओं को 'एक्सीलेंस अवार्ड' से सम्मानित किया। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया जब मंत्री ने एक शहीद आश्रित की पुत्री को 'उद्योग प्रसार अधिकारी' पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा।

कौशल विकास : ओडीओपी नीति के तहत 'कौशल वाहिनी- स्किल ऑन व्हील्स' को झंडी दिखाकर शिल्पकारों के प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया।

राजस्थान के उत्पाद अब सात समंदर पार परिचर्चा के दौरान महिला उद्यमियों ने अपने संघर्ष और सफलता की कहानियाँ साझा कीं। रान्जका गारमेंट की डेमा मित्तल ने बताया कि राजस्थान सरकार की निर्यात प्रोत्साहन नीति के सहयोग से उन्हें यूएसए (यूएसए) में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिला। इसके सुखद परिणाम स्वरूप अब उन्हें वहां से सीधे अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, जो राजस्थान के लघु उद्योगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

कोटा-बूंदी एयरपोर्ट का शिलान्यास | इस अवसर पर सीएम भजनलाल, लोकसभा अध्यक्ष बिरला और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू भी मौजूद रहे

पीएम मोदी ने निभाया वादा, 1500 करोड़ से संवरेगा हाड़ौती का भविष्य

कोटा (विशेष संवाददाता)। *हाड़ौती के विकास में शनिवार का दिन एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम के जरिए 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू भी मौजूद रहे।*

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भावुक होते हुए कहा, 'मैंने नवंबर 2023 में कोटा की जनता से जो वादा किया था, आज उसे पूरा करने की गारंटी दे रहा हूँ। अब कोटा के युवाओं और नागरिकों को विमान सेवा के लिए जयपुर या जोधपुर के

चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 'प्रधानमंत्री ने कोटा की बहुआयामी पहचान को रेखांकित करते हुए इसे देश का अनूठा 'एनर्जी हब' बताया। उन्होंने कहा कि कोटा एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ परमाणु, कोयला, गैस और जल-चारों स्रोतों से बिजली पैदा होती है।

धार्मिक पर्यटन: *नए एयरपोर्ट से श्री मथुराधीश जी, केशवराय पाटन, खड़े गणेश जी और गोदावरी बालाजी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए राह आसान होगी।*

औद्योगिक क्रांति: *हवाई कनेक्टिविटी से यह क्षेत्र 'Agro-based Industry' (कृषि आधारित उद्योगों) का बड़ा केंद्र बनेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे।*

सदन के 'मुखिया' की सराहना : *प्रधानमंत्री ने कोटा के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जमकर तारीफ की। उन्होंने बिरला को एक ऐसा जनसेवक बताया जो न केवल अपने क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित है, बल्कि सदन में 'अहंकारी और उत्पाती' तत्वों के कड़वे बोल सहकर भी सबको साथ लेकर चलते हैं। पीएम ने कहा कि बिरला जी ने संवैधानिक मर्यादाओं को नई ऊँचाई दी है।*

कनेक्टिविटी का महाजाल : *पीएम मोदी ने क्षेत्र में हो रहे बुनियादी ढांचागत सुधारों का ब्यौरा देते हुए बताया कि हाड़ौती अब कनेक्टिविटी का हब बन रहा है-*

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे : *इसके कारण दिल्ली, मुंबई और वडोदरा की दूरी अब घंटों में सिमट गई है।*

अमृत भारत स्टेशन : *कोटा संभाग के प्रमुख स्टेशनों का कायाकल्प कर उन्हें एयरपोर्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है।*

प्रधानमंत्री के संबोधन की 10 बड़ी बातें

मुख्य बिंदु	प्रधानमंत्री का संदेश
1. वादे की गारंटी	नवंबर 2023 का वादा आज शिलान्यास के साथ पूरा हुआ।
2. बजट	1500 करोड़ का प्रोजेक्ट क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलेगा।
3. बड़ी राहत	अब फ्लाइट के लिए जयपुर या जोधपुर जाने की मजबूरी खत्म।
4. ऊर्जा केंद्र	कोटा को ऊर्जा के सभी स्रोतों वाला 'अनूठा केंद्र' बताया।
5. आस्था	प्रमुख तीर्थस्थलों तक श्रद्धालुओं की पहुँच सुगम होगी।
6. मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी	एक्सप्रेसवे, रेलवे और अब एयरपोर्ट से ट्रिपल इंजन विकास।
7. रोजगार	एग्रो-इंडस्ट्री के जरिए युवाओं के लिए नए रास्ते खुलेंगे।
8. ओम बिरला की तारीफ	कोटा के विकास के लिए उनके निरंतर प्रयासों को सराहा।
9. संसदीय निष्ठा	बिरला को पक्ष-प्रतिपक्ष से ऊपर शानदार अध्यक्ष बताया।
10. धैर्य की जीत	विपरीत परिस्थितियों में भी सबको साथ लेकर चलने की कला।

समाचार पत्र 'द पब्लिक हब' के समस्त संपादकीय एवं प्रकाशकीय विषयों पर स्वायत अधिकार सहित प्रकाशक, स्वामी व संपादक: दीपक गोस्वामी,
ए-101 यूनिक टावर, प्रताप नगर, जयपुर-302017, मो. 9828528666 मुद्रक: अम्बर ऑफसेट प्रा. लि., जयपुर info@thepublichub.in, digital@thepublichub.in,
*पीआरबी एक्ट के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार।

भारत ने फाइलन में कीवियों को हराकर रचा इतिहास

तीसरा बार जीता टी-20 वर्ल्ड कप

न्यूजीलैंड को 96 रनों से दी शिकस्त, सैमसन प्लेयर ऑफ द सीरीज, बुमराह बने मैन ऑफ दी मैच

अहमदाबाद (एजेंसी)। संजू सैमसन (89), इशान किशन (54) और अभिषेक शर्मा (52) की विस्फोटक अर्द्धशतकीय पारियों के बाद भारतीय गेंदबाज जसप्रित बुमराह (4) और अक्षर पटेल के (3) विकेटों की दमदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। अहममदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में रविवार को न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। न्यूजीलैंड का ये फैसला गलत साबित हुआ। बल्लेबाजी करने उतरी भारत के लिए अभिषेक शर्मा और संजूसैम तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 7.1 ओवर में 98 रन जोड़े। आठवें ओवर की पहली गेंद पर रचिन रवींद्र ने

अभिषेक शर्मा को विकेट के पीछे कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में छह चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए 52 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए इशान किशन संजूसैमन के साथ दूसरे विकेट लिए 105 रनों की साझेदारी की। जिमी नीशम ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन को बाउंड्री पर कैच आउट करा दिया। संजूसैमन ने 46 गेंदों में पांच चौके और आठ छक्के उड़ाते हुए 89 रनों पारी खेली। इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर इशान किशन और आखिरी गेंद पर कप्तान सूर्यकुमार यादव (शून्य) को आउट कर न्यूजीलैंड की मैच में वापसी कराई। इशान किशन ने 25 गेंदों में चार चौके और चार छक्के लगाते हुए 54 रनों की पारी खेली। 19वें ओवर में मैट हेनरी ने हार्दिक पंड्या को आउट कर भारत को पांचवां झटका दिया। हार्दिक पंड्या ने 13 गेंदों में एक चौका और एक छक्का उड़ाते हुए 18 रन बनाये।

भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट पर 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। शिवम दुबे ने आखिरी ओवर कर रहे जिमी नीशम के ओवर में 24 रन ठोक कर भारत का स्कोर 250 के पार पहुंचाया। शिवम दुबे ने आठ गेंदों में तीन चौके और दो छक्का उड़ाते हुए नाबाद 28 रनों की तूफानी पारी खेली। तिलक आठ रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के लिए जिमी नीशम ने तीन विकेट लिए। रचिन रवींद्र और मैट हेनरी ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

खेल संक्षिप्त

ली ताहुहू ने 15 साल के करियर के बाद एकदिवसीय क्रिकेट से लिया संन्यास

वेलिंगटन (एजेंसी)। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज ली ताहुहू ने 15 साल के करियर के बाद एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट वेबसाइट के अनुसार 2011 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20

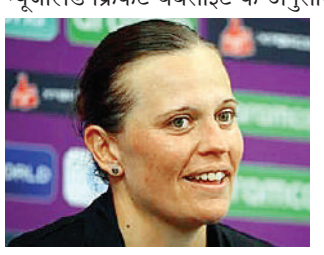

साल की उम्र में एकदिवसीय क्रिकेट में पर्दापण करने वाली ताहुहू ने 103 एकदिवसीय मैच में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने सफेद गेंद प्रारूप में 125 विकेट लिए हैं। ताहुहू उन 12 खिलाड़ियों में से हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड की महिला टीम के लिए 100 से अधिक एकदिवसीय मैच खेले हैं और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के चार एडिशन का हिस्सा रही हैं। 2023 में महिला एकदिवसीय टीम ऑफ द ईयर चुनी गई ताहुहू ने कहा कि अब 50 ओवर के प्रारुप से दूर जाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि एकदिवसीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड को शर्ट पहनना हमेशा से मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात रही है। एक गेम खेलना एक कमाल का एहसास था। एकदिवसीय क्रिकेट में 100 से अधिक बार शर्ट पहनना और अपने देश और अपने परिवार को रिप्रेजेंट करना, ऐसा कुछ है जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं हर पल को संजो कर रखूंगी और वनडे गेम से इस फॉर्मेट में जो कुछ भी हासिल कर पाई हूं, उस पर बहुत गर्व के साथ जाऊंगी। न्यूजीलैंड टीम के मुख्य कोच बेन सॉयर ने टीम में उनके शानदार योगदान और एकदिवसीय क्रिकेट में उनके शानदार रिकॉर्ड के लिए ताहुहू की तारीफ की।

सैमसन का कैच छोड़कर मैंने बड़ी गलती की : ब्रूक

नई दिल्ली (एजेंसी)। संजू सैमसन ने वानखेड़े में शोरगुल भरी रात में अपनी पहली छह गेंदों पर 15 रन बना लिए थे, लेकिन सातवीं गेंद को उन्होंने सीधा मिड-ऑन की ओर हवा में खेल दिया। यह ऐसा कैच था, जिसे हैरी ब्रूक 100 में से 99 बार पकड़ सकते थे। लेकिन इस बार उनसे गलती हो गई। उन्होंने न तो छलांग लगाई और न ही स्थिर रहे और गेंद उनके दाएं हाथ से छिटककर जमीन पर गिर गई। ब्रूक आधे आगे झुककर, घुटनों पर हाथ रखे, च्युइंग गम चबाते हुए खड़े थे और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी-अभी उनसे क्या हो गया है। ब्रूक को तुरंत समझ आ गया कि उनका यह छोड़ा हुआ कैच कितना महंगा पड़ सकता है। सैमसन ने अगली 35 गेंदों में 74 और रन जोड़कर भारत को 250 की ओर पहुंचा दिया।

ली शि फेंग को हराकर लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड सेमीफाइनल में

बर्मिंघम (एजेंसी)। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में दुनिया के नंबर 6 खिलाड़ी ली शि फेंग को सीधे गेम में हराकर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 12वीं रैंक वाले भारतीय शटलर ने यूटिलिटा एरिना बर्मिंघम में शुक्रवार को एक घंटे तक चले पुरुष एकल मुकाबले में चीन के ली को 21-13, 21-16 से हराया। यह जीत सेन के लिए खास तौर पर संतोषजनक थी, जिन्हें पिछले साल के टूर्नामेंट के इसी स्टेज में ली शि फेंग ने नॉकआउट कर दिया था। लक्ष्य ने शुरुआती गेम में दबदबा बनाया और पहले इंटरवल में पांच पॉइंट की बढ़त के साथ एंट्री की।

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने टेस्ट मैच में भारत को 10 विकेट से हराया

पर्थ (एजेंसी)। ऐनाबेल सदरलैंड (कुल छह विकेट और 129 रन) के हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन रविवार को भारतीय टीम को दूसरी पारी में 129 रन पर ढेर करने बाद मिले 25 रनों के लक्ष्य को 4.3 ओवर में हासिल कर मुकाबला 10 विकेट से अपने नाम कर लिया।

आज यहां भारतीय महिला टीम ने कल के छह विकेट पर 105 रनों से आगे खेलना शुरु किया। सुबह के सत्र में एश्ले गार्डनर ने स्नेह राणा (30) को

आउट कर भारत को सातवां झटका दिया। अगले ही ओवर में अलाना किंग ने काश्वी गौतम (शून्य) का शिकार कर लिया। सायली सातघरे (तीन) को भी अलाना किंग ने 48वें ओवर में आउट किया। अगले ही ओवर में एश्ले गार्डनर ने एक छोर थामे रन बना रही प्रतिका रावल को आउट कर भारत की दूसरी पारी का 149 के स्कोर पर अंत कर दिया। प्रतिका रावल ने भारतीय टीम के लिए सर्वाधिक 63 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 137 गेंदों का सामना किया और आठ चौके लगाये। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 25 रनों का लक्ष्य मिला। ऑस्ट्रेलिया की ओर से लूसी हैमिल्टन ने तीन विकेट लिये। ऐनाबेल सदरलैंड, अलाना किंग और एश्ले गार्डनर को दो-दो विकेट मिले। डार्सी ब्राउन ने एक बल्लेबाज को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में महज 4.3 ओवरों में बिना कोई विकेट गंवाए। 28 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। जॉर्जिया वॉल (16) और फीबी लिचफील्ड (11) रन बनाकर नाबाद रही।

हमने बहु-प्रारुप सीरीज मजबूत शुरुआत की लेकिन टेस्ट में लय नहीं बनाए रख सके : हरमनप्रीत

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि हमने बहु प्रारूप सीरीज में मजबूत शुरुआत की, लेकिन वाका ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में लय बनाए नहीं रख सके और मुकाबला हार गए। टेस्ट में मिली हार के बाद कौर ने कहा कि हमने बहुत अच्छी शुरुआत की, टी-20 में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन दुर्भाग्य से, उसके बाद, हम इसे जारी नहीं रख पाए, लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर यह एक अच्छी सीरीज थी। ऑस्ट्रेलिया में हर समय खेलकर बहुत खुश हूं, और मुझे लगता है कि यह एक शानदार मुकाबला था। उन्होंने कहा कि मल्टी-फॉर्मेट सीरीज और पिंक-बॉल टेस्ट खेलना टीम के लिए एक कीमती अनुभव था।

वर्ल्डकप हार का गुस्सा पाक ने वनडे टीम पर उतारा, 6 अनकैप्ड प्लेयर्स को मौका

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी-20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम के खराब प्रदर्शन का गुस्सा वनडे टीम पर उतारा। बुधवार को बांग्लादेश सीरीज के लिए टीम अनाउंस हुई। वर्ल्ड कप में बुरी तरह फ्लॉप रहे पूर्व कप्तान बाबर आजम और सईम अयूब को टीम से बाहर कर दिया। टीम में 6 अनकैप्ड प्लेयर्स और वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर रहे साहिबजादा फरहान को शामिल कर लिया। फरहान ने अक्टूबर 2024 से कोई घरेलू लिस्ट-ए मैच भी नहीं खेला है। वे अब तक पाकिस्तान के लिए वनडे डेब्यू भी नहीं कर सके।

शाहीन ही कप्तानी करेंगे: तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ही पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। उन्हें पिछले साल ही मोहम्मद रिजवान के बाद कप्तान बनाया गया था। वर्ल्ड कप टीम से बाहर रहे विकेटकीपर रिजवान वनडे टीम में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे। टी-20 कप्तान सलमान अली आगा, ऑलराउंडर फहीम अशरफ और लेग स्पिनर अबरार अहमद को भी टीम में जगह मिल गई।

6 अनकैप्ड प्लेयर्स को मौका

वनडे सीरीज में कई प्लेयर्स को डेब्यू का मौका मिल सकता है। 28 साल के अब्दुल समद को जगह मिली, जिन्होंने टी-20 क्रिकेट में फिनिशर के रूप में पहचान बनाई। 21 साल के शामिल हुसैन और और 20 साल के माज सदाकत भी स्क्वॉड का हिस्सा हैं।

3 लिस्ट-ए मैच खेलने वाले 21 साल के शाद मसूद और गाजी घोरी भी टीम में शामिल किए गए हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अनुभव को मौका अबरार के अलावा बॉलिंग डिपार्टमेंट में मोहम्मद वसीम जूनियर और हारिस रऊफ शामिल किए गए। बैटिंग ऑलराउंडर हुसैन तलत के साथ चाइनामैन फैसल अकरम भी टीम का हिस्सा हैं, जिन्होंने 2024 में वनडे डेब्यू किया था।

इस बार सविता पूनिया नहीं खेलेगी हॉकी वर्ल्ड कप क्वालीफाई

सिरसा (एजेंसी)। सिरसा जिले की रहने वाली अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सविता पूनिया इस बार हॉकी वर्ल्ड कप क्वालीफाई नहीं खेलेगी। वह इस वक्त कैंप में भी हिस्सा नहीं ले रही। इस वर्ल्ड कप क्वालीफाई के लिए टीम खिलाड़ियों का चयन हो चुका है और खिलाड़ी अपनी तैयारी में जुटी हैं। यह वर्ल्ड कप क्वालीफाई भारत में ही होगा। 8 मार्च से हैदराबाद में शुरू प्रतियोगिताएं शुरू होगी, जो 14 मार्च तक चलेगी। इसमें चार देशों की टीमें भाग लेंगी।

जानकारी के अनुसार, हॉकी वर्ल्ड कप लेकर बैंग्लोर में कैंप चल रहा है, जहां

पर खिलाड़ियों को तैयारी करवाई जा रही है। पूरी टीम पिछले लंबे समय से तैयारी कर रही है। सविता ने भी पहले यहां पर ट्रेनिंग ली, पर अब इसमें हिस्सा नहीं ले रही। सविता पूनिया के पिता महेंद्र सिंह ने इसकी वजह परिवारिक कारण बताया है।

अब सविता पूनिया इस माह के अंत तक कैंप में वापसी करेगी और एशियन गेम्स ही उनका लक्ष्य है। ऐसे में एशियन गेम्स की तैयारी जल्द शुरू करेगी। हालांकि, सविता का नाम पदमश्री अवार्ड की सूची में भी आ गया है। इसकी परिवार सहित गांव व पूरे जिले में खुशी मनाई गई। उनको राष्ट्रपति की ओर से सम्मानित किया जाएगा। सविता सिरसा के जोधकां गांव स्थित अपने घर आई थी और परिवार के साथ पदमश्री अवार्ड का जश्न मनाया।

अफगानिस्तान के नए टी-20 कप्तान बने जादरान

नई दिल्ली (एजेंसी)। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इब्राहिम जादरान को टी-20 इंटरनेशनल टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। जादरान स्टार स्पिनर राशिद खान की जगह ली है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी टी-20 और वनडे सीरीज के लिए गुरुवार को अपनी टीमें घोषित कर दीं। बोर्ड के मुताबिक, जादरान अब टी-20 फॉर्मेट में टीम की अगुआई करेंगे और उनकी कप्तानी का पहला असाइनमेंट श्रीलंका के खिलाफ सीरीज होगी। जादरान उपकप्तान भी रह चुके राशिद खान लंबे समय से अफगानिस्तान की टी-20 टीम की कप्तानी कर रहे थे।

रैंडेल ने 5 गेंदों में झटके पांच विकेट

नेपियर (एजेंसी)। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के तेज गेंदबाज ब्रेट रैंडेल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पांच गेंदों में लगातार पांच विकेट लेकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। ब्रेट रैंडेल ने रविवार को यह कारनामा प्लंकेट शील्ड मैच के दूसरे दिन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ मुकाबले में किया है। इसी के साथ वह प्रथम श्रेणी में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले गेंदबाज बन गए। रैंडेल का स्पेल इतना खतरनाक रहा कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने केवल नौ के स्कोर पर ही अपने पांच विकेट गंवा दिए। रैंडेल ने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर हेनरी कूपर को आउट करते हुए विकेट लेने का यह सिलसिला शुरू किया। अगले ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने राउंड द विकेट से आकर जीत रावल की गिल्लियां बिखेर दीं। दूसरी गेंद पर जो कार्टर को विकेट के पीछे कैच कराते हुए उन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी की। रॉबर्ट ओ'डॉनेल ने अगली गेंद पर स्लिप में कैच थमाया। क्रिस्टियन क्लार्क ने अगली गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला चलाया और गेंद अंदरुनी किनारा लेकर स्टंप में जा लगी। इस समय रैंडेल के गेंदबाजी आंकड़े 2.4-1-2-5 थे जिस पर भरोसा कर पाना बेहद मुश्किल था। थोड़ी ही देर बाद वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में आठ गेंदों में छह विकेट लेने वाले भी पहले गेंदबाज बने थे।

अपनी उपलब्धि पर रैंडेल ने कहा कि मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। यह ऐसा लम्हा था जब मुझे लगा कि कोई आकर मुझे पिंच करे। मैं एकाग्र रहकर गेंद को एक ही जगह गिराने की कोशिश कर रहा था और हैट्रिक के बाद भी मैंने वही करना जारी रखा। मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह पहली बार हुआ 'प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पांच गेंदों में पांच विकेट'। मेरे पास फिलहाल शब्द नहीं हैं। मैं ईमानदारी से कहूं तो मजा आया। रैंडेल को सात विकेट लेने के लिए केवल 3.5 ओवर ही लगे। उन्होंने 11 ओवर में 25 देकर सात विकेट झटक कर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम केवल 82 के स्कोर पर ढेर हो गई और पहली पारी में 373 रन बनाने वाली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने उन्हें फॉलोऑन दे दिया। टी-20 क्रिकेट में यह उपलब्धि कर्टिस कैम्फर के नाम है। उन्होंने डबलिन में मंस्टर रेड्स के लिए खेलते हुए नॉर्थ-वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ पांच गेंदों में पांच विकेट लिए थे।

एकदिवसीय मैच में जिम्बाब्वे को आठ विकेट से शिकस्त

मेली केर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सात विकेट लेकर रिकॉर्ड तोड़ा

डुनेडिन (एजेंसी)। मेली केर (34 रन देकर सात विकेट) के ऐतिहासिक गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड ने रविवार को डुनेडिन के यूनिवर्सिटी ओवल में दूसरे एकदिवसीय मैच में जिम्बाब्वे को आठ विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ केर ने जैकी लॉर्ड के 44 साल पुराने रिकार्ड को भी तोड़ दिया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। केर ने 34 रन देकर सात विकेट झटके और जिम्बाब्वे को मात्र 102 रन पर समेट दिया, जिससे जैकी लॉर्ड का 44 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया।

लॉर्ड ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1982 में भारत के खिलाफ 6/10 का रिकॉर्ड बनाया था, जो इससे पहले एकदिवसीय में न्यूजीलैंड की किसी महिला का सबसे अच्छा गेंदबाजी प्रदर्शन था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की वेबसाइट के अनुसार यह महिला

एकदिवसीय में सात विकेट लेने का सातवां मौका था। केर इस उपलब्धि के साथ पाकिस्तान की साजिदा शाह, इंग्लैंड की जो चेम्बरलेन, वेस्ट इंडीज की अनीसा मोहम्मद और ऑस्ट्रेलियाई तिकड़ी अलाना किंग, एलिस पेरी और शेली निट्स्के की सूची में शामिल हो गई। इससे पहले, मॉली पेनफोल्ड ने 17 रन देकर तीन विकेट लिए, जिससे जिम्बाब्वे का शीर्ष क्रम ध्वस्त हो गया और मेहमान टीम 48 रन पर तीन विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी। इसके बाद केर ने आक्रमण की जिम्मेदारी को संभाला और सी धुरुरू को बोल्ड करके टीम को गिराना शुरू किया। उन्होंने मोडेस्टर मुपाचिकवा, क्रिस्टाबेल चैटोंजवा, एडेल जिमुनु, न्याशा ग्वानज़ुरा, ऑड्रे माजविशाया और तेंदई मकुशा को जल्दी-जल्दी आउट किया, जिससे मेजबान टीम ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। केर ने बल्ले से भी अहम योगदान दिया, लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने सबसे अधिक 45 रन बनाए, जिससे न्यूजीलैंड ने आराम से आठ विकेट से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की महिला टीम ने तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।

सेहत का 'मैजिक मंत्र'

रोजाना 30 मिनट की सैर से दिल-दिमाग रहेंगे जवां

सुस्त जीवनशैली और डेस्क जॉब के खतरों को कम करने का सबसे आसान तरीका, जानें 'ब्रिस्क वॉकिंग' के 12 बड़े फायदे

आजकल *की डेस्क जॉब, सुस्त जीवनशैली और ऑनलाइन सुविधाओं ने हमारे चलने-फिरने को सीमित कर दिया है। इसका सीधा असर हमारे दिल, दिमाग और हड्डियों पर पड़ रहा है।*

स्वास्थ्य *विशेषज्ञों और हालिया शोधों के अनुसार, इन खतरों से बचने का सबसे सरल उपाय है-रोजाना 30 मिनट की सैर। 'ब्रिस्क वॉकिंग' (तेज चाल) न केवल वजन घटाने में मदद करती है, बल्कि यह अल्जाइमर और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों के जोखिम को भी आधा कर सकती है।*

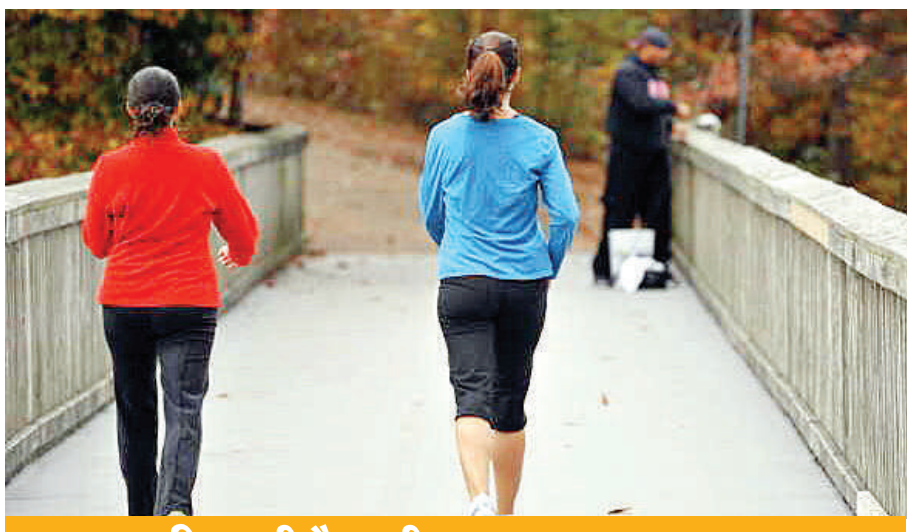

क्या है चलने का सही तरीका? (ब्रिस्क वॉक)

सैर का पूरा लाभ उठाने के लिए केवल टहलना काफी नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, आपको 'ब्रिस्क वॉक' करनी चाहिए।

पहचान : आपकी गति इतनी तेज होनी चाहिए कि आप चलते समय बात तो कर सकें, लेकिन गाना गाने में आपकी सांस फूलने लगे।

समय का प्रबंधन : यदि आप एक साथ 30 मिनट नहीं निकाल सकते, तो दिन भर में 10-10 मिनट के तीन राउंड भी उतने ही प्रभावी होते हैं।

जीवनशैली में कैसे शामिल करें पैदल चलना?

व्यस्तता के बावजूद आप इन आसान तरीकों से अपने कदम बढ़ा सकते हैं-

फोन कॉल के दौरान टहलें : मोबाइल पर बात करते समय बैठने के बजाय कमरे या ऑफिस में वॉक करें।

सीढ़ियों का चुनाव : लिफ्ट या एस्केलेटर के बजाय हमेशा सीढ़ियों का उपयोग करें।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट : बस या ऑटो से थोड़ा पहले उतरें और बाकी रास्ता पैदल तय करें।

शुरुआत धीमी रखें : यदि आप पहली बार शुरू कर रहे हैं, तो पहले अपनी गति सामान्य रखें और धीरे-धीरे इसे 'ब्रिस्क वॉक' में बदलें।

निष्कर्ष : मजबूत शरीर और स्वस्थ दिमाग स्थिर आदतों से ही बनते हैं। रोजाना महज 30 मिनट का निवेश आपके बुढ़ापे को सुखद और रोगमुक्त बना सकता है।

30 मिनट की सैर : शरीर पर 12 सकारात्मक प्रभाव

स्वास्थ्य लाभ	विवरण और प्रभाव
मजबूत हृदय	स्ट्रोक का खतरा 20% से 40% तक कम होता है; ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है।
स्मृति और दिमाग	अल्जाइमर का जोखिम 50% तक कम होता है; याददाश्त में गिरावट को धीमा करता है।
मजबूत हड्डियां	कूल्हे की हड्डी टूटने का जोखिम 40% कम; ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव।
वजन नियंत्रण	30 मिनट की तेज चाल से लगभग 200 कैलोरी बर्न होती है।
बेहतर मूड	शरीर में 'एंडोर्फिन' (प्राकृतिक पेनकिलर) रिलीज होता है, जिससे तनाव कम होता है।
लंबा जीवन	नियमित वॉक करने वालों में मृत्यु की संभावना 35% तक कम हो जाती है।
गहरी नींद	सुबह की सैर अनिद्रा (Insomnia) की समस्या को दूर करने में सहायक है।
जोड़ों को सहारा	जोड़ों के कार्टिलेज को पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलते हैं, जिससे जोड़ों का दर्द कम होता है।
श्वसन तंत्र	फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह तेज होता है।
मांसपेशियां	पैर, पेट और बाहों की मांसपेशियां टोन और मजबूत होती हैं।
ब्लड सर्कुलेशन	पूरे शरीर में रक्त का संचार सुधरता है, जिससे अंगों की कार्यक्षमता बढ़ती है।
विकलांगता से बचाव	उम्रदराज लोगों में दैनिक कार्यों को करने की क्षमता बनी रहती है।

सी-सेक्शन के बाद व्यायाम करने के होते हैं काफी लाभ

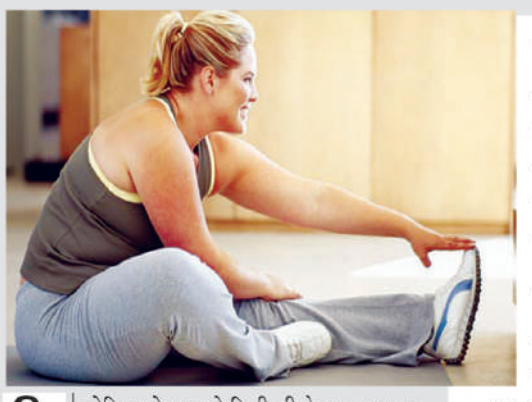

सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी के बाद सामान्य स्थिति में आने में वक्त लगता है। एक अनुमान के मुताबिक डिलीवरी के बाद महिला को नॉर्मल होने में लगभग 18 महीने लग जाते हैं। क्योंकि इस दौरान महिला अपने स्वास्थ्य से ज्यादा अपने बच्चे पर ध्यान देती है और अक्सर वह रात-रात भर जागकर उसकी देखभाल करती है। सिजेरियन के बाद ज्यादा व्यायाम और एक्सरसाइज भी नही किया जा सकता है। क्योंकि महिला के पेट में कई टांके लगे होते हैं और व्यायाम करने से मांसपेशियां में खिंचाव होता है और उनका सीधा असर चीरों पर पड़ता है। सी-सेक्शन से प्रसव के बाद खान-पान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सिजेरियन के कुछ सप्ताह बाद आप व्यायाम शुरू कर सकती हैं। आइए हम आपको इस समय किये जाने वाले व्यायाम के कुछ टिप्स के बारे में बताते हैं जो आपको फिट रखने में मदद करेंगे।

सी-सेक्शन के बाद व्यायाम के टिप्स डॉक्टर से संपर्क कीजिए

सिजेरियन के बाद आप खुद से व्यायाम करने का निर्णय मत लीजिए। कोई भी शारीरिक गतिविधि करने से पहले चिकित्सक से संपर्क कीजिए। पहले यह निश्चित कर लीजिए कि आपका शरीर व्यायाम करने के लायक हुआ है या नही। सिजेरियन के दौरान जो घाव हुए थे वो सामान्य हुए हैं या नहीं। इन सबकी जांच करवाने के बाद ही आप व्यायाम शुरू कीजिए। यदि आपका शरीर सामान्य है तो आपका चिकित्सक आपको व्यायाम करने की सलाह देगा।

कीगल्स एक्सरसाइज

यह व्यायाम आपके पेट को कम करने में मदद कर सकता है। आप इस व्यायाम को दिन में दो से तीन बार कर सकती हैं। इससे आपके पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह व्यायाम जमीन पर लेटकर किया जाता है।

पिलातेस एक्सरसाइज

पिलातेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान व डिलवरी के बाद भी करती हैं। पिलातेस से महिलाएं चुस्त दुरुस्त रहती हैं। कई महिलाओं ने इस एक्सरसाइज को किया और पाया कि अन्य व्यायामों के मुकाबलें इसमें पेट, पीठ, श्रोणि व अन्य मांसपेशियों की अच्छी एक्सरसाइज होती है। सी-सेक्शन के बाद इस व्यायाम को आप कर सकती हैं। इससे आपके पेट की अतिरिक्त चर्बी भी कम हो जाएगी।

थोड़ा टहलें

सिजेरियन के बाद आप घर के आसपास टहल सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान आप जॉगिंग बिलकुल न करें। धीरे-धीरे घर के आसपास का चक्कर लगाइए। शुरूआत में केवल 10 मिनट टहलिए बाद में इसे बढ़ाकर 30 मिनट कर सकती हैं। इससे आपके शरीर में रक्त संचार बढ़ेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगी।

व्यायाम का समय

हालांकि सिजेरियन के बाद कितनी देर व्यायाम करना चाहिए, इसके लिए समय निर्धारित नही है लेकिन इसके लिए आप अपने चिकित्सक से सलाह अवश्य लीजिए। चिकित्सक के सलाह अनुसार ही व्यायाम का समय निर्धारित कीजिए। सकारात्मक सोच रखिए और अपनी तुलना किसी अन्य महिला से बिलकुल मत कीजिए। यदि आपका पेट निकला हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नही है, धीरे-धीरे एक्सरसाइज करने से भी आप कुछ दिनों बाद अपने बॉडी को पुराने शेप में ढाल सकती हैं।

सिजेरियन के बाद अपने डाइट पर ध्यान दीजिए। अपनी डाइट चार्ट में ऐसे खाद्य-पदार्थ शामिल कीजिए जो मिनरल और विटामिन से भरपूर हों। नियमित रूप से जांच करवाते रहिए और चिकित्सक से सलाह अवश्य लीजिए।

ईरान संघर्ष के बीच भारत ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोतों का रुख किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के लंबा खिंचने की आशंका के बीच भारतीय खुदरा ईंधन कंपनियों ने अमेरिका, रूस और पश्चिम अफ्रीका से अतिरिक्त कच्चे तेल के लिए बातचीत शुरू कर दी है। उद्योग अधिकारियों और विश्लेषकों ने यह जानकारी दी।

कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों में परिशोधित करने वाली रिफाइनरियों ने फिलहाल अपनी प्रस्तावित मरम्मत बंदी को टाल दिया है और सामान्य परिचालन दर बनाए रखी है ताकि देश की तात्कालिक जरूरतों के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक बना रहे। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 88 प्रतिशत आयात करता है। फरवरी में इस आपूर्ति का लगभग आधा

हिस्सा 'होर्मुज जलडमरूमध्य' से होकर आया था, जो ईरान और ओमान के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण इस रणनीतिक मार्ग से टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि हम उन क्षेत्रों से अधिक आपूर्ति ले रहे हैं जो संघर्ष क्षेत्र से बाहर हैं। वर्ष 2025 में गैर-होर्मुज स्रोतों की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई है।

भारतीय रिफाइनरियां अब पश्चिम अफ्रीका, लातिन अमेरिका और अमेरिका से तेल ले रही हैं। साथ ही, अमेरिकी ट्रेजरी (वित्त) विभाग द्वारा रूसी तेल की बिक्री और वितरण के लिए दी गई 30 दिनों की छूट ने एक नया रास्ता खोल दिया है। इस छूट के तहत पांच मार्च तक जहाजों पर लदे रूसी तेल को पांच अप्रैल तक बिना प्रतिबंधों के भारत पहुंचने की अनुमति दी गयी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल और एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड जैसी कंपनियों ने रूसी तेल की खरीद फिर से शुरू कर दी है। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारत की स्थिति मजबूत है और वर्तमान भंडार देश की 50 दिनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि भारत के पास वर्तमान में लगभग 14.4 करोड़ बैरल कच्चा तेल भंडारण में है और महत्वपूर्ण बात यह है कि तेल की इस आपूर्ति की निरंतर भरपाई की जा रही है।

पीएनबी धोखाधड़ी मामला

सीबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ दर्ज किया नया केस

नई दिल्ली (एजेंसी)। सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर रिलायंस कम्युनिकेशंस के प्रमुख अनिल अंबानी के खिलाफ 1,085 करोड़ रुपए की ऋण धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का एक नया मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पीएनबी के मुख्य प्रबंधक संतोषकृष्ण अन्नावरपु की एक शिकायत के आधार पर की गई है। समाचार एजेंसी के पास मौजूद इस प्राथमिकी की प्रति के अनुसार, इसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2013 से 2017 के बीच अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के तत्कालीन अधिकारियों ने कथित तौर पर पीएनबी के साथ 1,085 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। बैंक का आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने यह कर्ज वापस न करने की नीयत से प्राप्त किया। पीएनबी ने दावा किया कि कंपनी ने बैंक से प्राप्त धन को जानबूझकर अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा करना धोखाधड़ी और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के समान है।

पीएनबी ने एटीएम से कैश निकालने की लिमिट 50 फीसदी घटाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने चुनिंदा डेबिट कार्ड्स से रोजाना कैश निकालने की लिमिट को आधा कर दिया है। नए नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। बैंक ने यह फैसला रिस्क कंट्रोल को मजबूत करने और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिया है।

1 लाख वाली लिमिट अब 50,000 हुई : पीएनबी ने अपने डेबिट कार्ड्स को दो मुख्य कैटेगरी में बांटकर लिमिट रिवाइज की है। जिनकी डेली लिमिट पहले 1 लाख रुपए थी, इसे अब 50 हजार रुपए कर दिया है। वहीं दूसरी कैटेगरी में प्रीमियम कार्ड्स की लिमिट 1.5 लाख रुपए से घटाकर 75 हजार रुपए कर दी गई है। बैंक ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि यह बदलाव सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। बैंक का मानना है कि कैश निकालने की लिमिट कम होने से फ्रॉड के मामलों में ग्राहकों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा।

ब्लेंडर्स प्राइड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर ने 'द वन एंड ओनली' किया लॉन्च

कोटा (द पब्लिक हब)। ब्लेंडर्स प्राइड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, जिसने कई पीढ़ियों से सफलता के मायने को नई ऊंचाई दी है, अपना नया कैंपेन 'द वन एंड ओनली' लेकर आया है- सफलता की एक नई और प्रभावशाली कहानी। आज के समय में, जब सफलता के कई रूप दिखाई देते हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, तब ब्रांड एक सरल सच सामने लाता है - असली सफलता अलग पहचान में होती है, जो लोगों की प्रशंसा पाती है और व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है। इस नए कैंपेन में इस भावना को तीन चेहरों अवंती नगरथ, किरनदीप चहल और माहका शर्मा के जरिए दिखाया गया है। ये तीनों ब्रांड के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। अवंती अपने निडर आत्मविश्वास और अलग अंदाज से आकर्षण पैदा करती हैं, किरनदीप अपनी प्रभावशाली और बेबाक मौजूदगी से लोगों को प्रभावित करती हैं, और माहिका अपने संतुलित और शांत व्यक्तित्व से प्रेरणा देती हैं।

एसी की कीमतों में लगी आग

नई दिल्ली (एजेंसी)। कमरे को ठंडा रखने वाले एयर कंडीशनर बनाने वाली प्रमुख कंपनियां कच्चे माल की लागत और आपूर्ति श्रृंखला के खर्चों में निरंतर वृद्धि की भरपाई के लिए कीमतों में 5-15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर रही हैं। फरवरी से अप्रैल के बीच लागू की जा रही यह बढ़ोतरी ठीक उस समय हो रही है, जब गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ एयर कंडीशनर (एसी) की मांग बढ़ने वाली है। डाइकिन, वोल्टास, ब्लू स्टार, एलजी, हायर और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज सहित प्रमुख कंपनियों ने विभिन्न मॉडलों की कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है।

सोनालीका ने सर्वाधिक 12,890 कुल ट्रैक्टर बिक्री दर्ज की

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में कृषि मशीनीकरण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के अपने 30वें ऐतिहासिक वर्ष में, सोनालीका ट्रैक्टर्स ने एक और सुनहरा अध्याय जोड़ते हुए वित्त वर्ष-26 में फरवरी माह की अब तक की सर्वाधिक 12,890 ट्रैक्टरों की कुल बिक्री दर्ज की है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि बड़े स्तर पर मजबूत कार्या नीति और कंपनी के मूल विश्वास 'जीतने का दम' का प्रमाण है - जो किसानों के उज्ज्वल भविष्य की ताकत है।

आज जब देश में आधुनिक कृषि तकनीक से उन्नत और किफायती कृषि रही है, सोनालीका इनोवेशन, किसानों से गहरा जुड़ाव और मजबूत बाजार पहुंच के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। इस नई उपलब्धि पर अपने विचार साझा करते हुए, रमन मित्तल, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, ने कहा, 'असली 'जीतने का दम' हमेशा उन किसानों में रहा है, जो हर दिन अपने खेतों में प्रगति बोते हैं। हमारी

जिम्मेदारी है कि हम ऐसे हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर तैयार करें जो किसानों के सपनों और उनकी सफलता के संकल्प को और मजबूत बनाएं। 30वें वर्ष के फरवरी माह में 12,890 ट्रैक्टरों की रिकॉर्ड बिक्री हमारे लिए बेहद खास है।

यह उपलब्धि भारत के कृषि परिवर्तन में हमारी भूमिका को और मजबूत करती है और हमें किसानों की प्रगति को देश की समृद्धि से जोड़ने की नई प्रेरणा देती है।

सैमसंग की गैलेक्सी एस 26 सीरीज से प्राइवेसी-एआई के दौर की शुरुआत

गुरुग्राम (एजेंसी)। सैमसंग ने अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी एस 26 अल्ट्रा पेश किया है। इस स्मार्टफोन में दिया गया नया 'प्राइवेसी डिस्प्ले' फीचर पूरी टेक दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है और इसे हर तरफ से काफी सराहना मिल रही है।

सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट और सीईओ जेबी पार्क ने कहा कि यह उद्योग में अपनी तरह का पहला फीचर है, जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में प्राइवेसी के एक नए दौर की शुरुआत करता है। उन्होंने कहा, 'चूंकि अब हम एआई के दौर में हैं, इसलिए गैलेक्सी एस 26 सीरीज में प्राइवेसी को और भी

बेहतर बनाया गया है। थर्ड-पार्टी फिल्टर के विपरीत, 'प्राइवेसी डिस्प्ले' सीधे स्क्रीन के अंदर ही शामिल है। इससे रोजमर्रा के इस्तेमाल में स्क्रीन देखने का अनुभव पहले जैसा ही शानदार रहता है, जबकि साइड एंगल से स्क्रीन पर क्या चल रहा है, यह दिखाई नहीं देता।

यूजर प्राइवेसी को स्क्रीन के किसी खास हिस्से तक सीमित कर सकते हैं या यह भी तय कर सकते हैं कि यह फीचर कब सक्रिय हो। इससे आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा बहुत ही सहज और आसान हो जाती है।

तीन माह से घोटाले के टेंडर पर 'कुंडली' मारकर बैठे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी

360 करोड़ के आईसीटी लैब टेंडर में 'सौदेबाजी' का मामला

जयपुर (विशेष संवाददाता)। प्रदेश के शिक्षा विभाग में अधिकारियों की कमीशनखोरी का खेल सरकारी स्कूलों के बच्चों पर इतना भारी पड़ रहा है कि 2 साल से लाखों बच्चों की डिजिटल पढ़ाई का सपना टेंडरों में उलझकर ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। प्रदेश के 3213 सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब के लिए चौथी बार निकाला गया करीब 360 करोड़ की लागत का टेंडर 3 महिने बाद भी फाइल नहीं हुआ। फर्जीवाड़े व कमीशनखोरी के बड़े खेल से जुड़े इस टेंडर की शिकायत होने के बाद अधिकारियों ने खुद को फंसने से बचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से तो रोक दिया, लेकिन 3 महिने बाद भी टेंडर को निरस्त नहीं किया। जानकारी के अनुसार इस टेंडर को लेकर विभाग के अधिकारियों और ठेका कंपनियों के बीच सौदेबाजी हो जाने के कारण खुलेआम निविदा शर्तों एवं आरटीपीपी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कंपनियों को निविदा में सफल कर दिया गया। इस गंभीर फर्जीवाड़े को लेकर शिकायत होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी टेंडर प्रक्रिया पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार इस मामले को ठंडा पड़ने के बाद अब अधिकारी गली निकालकर चहेती फर्म को कार्यादेश जारी करने की तैयारी कर रहे हैं।

कंपनियों को फायदा पहुंचाने के बच्चों के केरियर से खिलावाड़ : शिक्षा विभाग की ओर से 06 अक्टूबर, 2025 को चौथी बार 3213 सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापना कार्य की निविदा संख्या-05/2025-26 आमंत्रित की गई। विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा खुद को करोड़ों का लाभ प्राप्त करने के लिए फिर से वहीं कहानी दोहरा दी। निविदा प्रक्रिया में चार कंपनियों ने भाग लिया और आनन-फानन में बिना दस्तावेजों की जांच किए ही सभी कंपनियों की तकनीकी बिड खोल दी। तकनीकी बिड में शामिल सभी कंपनियों के दस्तावेजों में गंभीर खामियां होने के बाद भी निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने की बजाए अधिकारी निविदा की वित्तीय बिड खोलने में जुटे हैं। विभाग के अधिकारियों ने चहेती ठेका कंपनियों के साथ खुद को करोड़ों का फायदा पहुंचाने के लिए न केवल निविदा प्रक्रिया को दूषित कर दिया, बल्कि 2 साल से सरकारी स्कूलों के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है।

सौदेबाजी के खेल का एसीबी में परिवाद दर्ज, शिक्षा शासन सचिव से मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट : जनवरी, 2025 में आमंत्रित की गई निविदा संख्या- 24/2024-25 में विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा खुद को करोड़ों का लाभ पहुंचाने के लिए नियम विरूद्ध तरीके से चहेती ठेका कंपनियों को मोटा फायदा पहुंचाने के खेल को लेकर एसीबी में शिकायत हुई थी, जिस पर एसीबी ने दिनांक- 03.11.2025 को परिवाद संख्या: सी-एचआर-42/2025 दर्ज किया गया है।

परिवार को लेकर एसीबी की ओर से सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि विभाग के अधिकारियों की ओर से अभी तक एसीबी को तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं भेजी गई, जिससे भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।

सौदेबाजी के चलते 3 बार पहले भी निरस्त हो चुका है टेंडर

विभाग की ओर से इससे पहले के जनवरी, 2025 में निविदा संख्या- 24/2024-25 आमंत्रित की गई थी, जिसे भी विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा खुद को करोड़ों का लाभ पहुंचाने के लिए नियम विरूद्ध तरीके से चहेती फर्मों को कार्यादेश देने के कूटरचित प्रयास किए जा रहे थे, जिसके चलते 8 महिने तक निविदा प्रक्रिया को लटकाए रखा था। विभाग के अधिकारियों और ठेका कंपनियों के इस मिलीभगत व सौदेबाजी के खेल की प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत पहुंची थी, जिसकी भनक लगते ही अधिकारियों ने आनन-फानन में निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। हालांकि इस निविदा को निरस्त करने के प्रकरण में आज दिनांक तक किसी भी संबंधित अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते इस मिलीभगत के खेल पर और भी ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं।

करोड़ों के एडवांश में फंसे अधिकारी, काम देना हुआ मजबूरी

सूत्रों के अनुसार 3213 सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापना का कार्य को लेकर विभाग के कुछ अधिकारियों और ठेका कंपनियों के बीच पहले से करोड़ों के एडवांश में लेनदेन हो चुका था, जिसके बाद विभाग की ओर से निविदा संख्या-24/2024-25 आमंत्रित कर ठेका कंपनी को काम दिया जाना था। लेकिन निविदा प्रक्रिया पर खुलेआम नियम व शर्तों की धज्जियां उड़ाने को लेकर गंभीर शिकायतें होने के बाद शिक्षा मंत्री के विरोध और पीएमओ तक शिकायतें पहुंचने के बाद इस निविदा को आनन-फानन में निविदा को निरस्त करना पड़ गया। निविदा के निरस्त हो जाने और आगे काम की संभावना नहीं दिखने पर ठेका कंपनी की ओर से करोड़ों के एडवांश का पैसा वापस लौटाने की डिमाण्ड करने से विभाग के अधिकारी भारी दबाव में आ गए। इसके बाद विभाग के अधिकारियों ने ठेका कंपनी को आश्वस्त किया कि जल्द ही निविदा प्रक्रिया फिर से शुरू होगी और काम दे दिया जाएगा।

अधिकारियों ने कंपनियों के लिए नियमों की उड़ाई धज्जियां

नई निविदा में सौदेबाजी का खेल उजागर नहीं हो इसलिए पिछली निविदा में भाग लेने वाली ठेका कंपनी Unbox Gadgets Pvt Ltd के स्थान पर नई निविदा में Hello Mobiles Pvt Ltd ने निविदा में भाग लिया, जबकि दोनों कंपनियों का रजिस्टर्ड पता House No: 2-56/2-33, Plot No. 1303, Near YSR Statue, Khanamet, Road No.- 48, Ayyappa Society-Madhapur, Hyderabad- 500081, Telangana एक ही है। शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी सौदेबाजी के बाद चहेती कंपनियों पर इस कदर मेहरबान है कि उक्त निविदा की शर्तों की पालना नहीं किए जाने के बाद भी कंपनियों की न केवल पद का दुरूपयोग करते हुए तकनीकी बिड खोल दी गई, बल्कि उन्हें अवैध तरीके से निविदा की तकनीकी बिड में पास कर उन्हें कार्य देने की योजना थी।

जैसलमेर वादर महोत्सव : मोहन भागवत ने किया शुभारंभ

मोहन भागवत बोले-भेदभाव मिटाकर एक परिवार बनें

871 साल बाद होगा पवित्र चादर का महाअभिषेक, एक करोड़ 8 लाख श्रद्धालु एक साथ करेंगे 'दादागुरु इकतीसा' का पाठ

जैसलमेर (विशेष संवाददाता)। सीमावर्ती जिले जैसलमेर के डेडानसर मैदान में शुक्रवार को तीन दिवसीय ऐतिहासिक 'चादर महोत्सव' का भव्य शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने गच्छाधिपति आचार्य जिनमणिप्रभ सुरीश्वर महाराज के सान्निध्य में इस विराट आयोजन की शुरुआत की। इस अवसर पर भागवत ने जैसलमेर किले में स्थित दादा जिनदत्त सूरि की अलौकिक चादर के दर्शन किए और धर्मसभा को संबोधित करते हुए सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश दिया।

धर्मसभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक एकता में दादागुरु परंपरा का अतुलनीय योगदान है। उन्होंने समाज से ऊंच-नीच के भेदभाव को जड़ से मिटाने का आह्वान किया।

11वीं शताब्दी का चमत्कार : जैसलमेर जैन ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र सिंह भंसाली ने इस पवित्र चादर के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 11वीं शताब्दी में प्रथम दादागुरु जिनदत्त सूरी के अग्नि-संस्कार के समय प्रचंड लपटों के बावजूद उनकी चादर सुरक्षित रही थी। लगभग डेढ़ सौ साल पहले महामारी को रोकने के लिए जैसलमेर के तत्कालीन महारावल ने इसे पाटन से मंगवाया था। यह अलौकिक चादर वर्तमान में सोनार दुर्ग के ज्ञान भंडार में सुरक्षित है और पहली बार सार्वजनिक दर्शन के लिए उपलब्ध हुई है।

वैश्विक महाअभियान : 30 हजार केंद्रों पर गूंजेगा पाठ

समिति के चेयरमैन और महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने इस आयोजन को 'आध्यात्मिक जागरण का वैश्विक महाअभियान' करार दिया। राष्ट्रीय संयोजक ज्योति कोठारी ने बताया कि 7 मार्च को होने वाले सामूहिक पाठ में विश्व हिंदू परिषद के 30 हजार केंद्रों, विद्या भारती के 1000 स्कूलों और देशभर की सभी दादाबाड़ियों के श्रद्धालु एक साथ जुड़ेंगे।

युवाओं को संस्कार का मार्ग दिखाएं संत : गच्छाधिपति जिनमणिप्रभ सूरि ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के चुनौतीपूर्ण समय में युवाओं को संयम और सदाचार का मार्ग दिखाना सबसे बड़ी आवश्यकता है। कार्यक्रम में पूर्व महारानी रासेश्वरी राज्य लक्ष्मी, आचार्य मनोज्ञ सागर सूरि सहित करीब 400 संतों की गरिमामयी उपस्थिति रही। महोत्सव के अगले चरणों में 'द यूनिवर्सल ट्रूथ' और 'गुरुदेव' पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा।

'दुनिया में झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी वास्तविक एकता को नहीं पहचान पाते। हमें सभी प्रकार के भेदभाव भूलकर एक ही परिवार बनना होगा— जो सुख-दुख में साथ रहे, साथ बैठे और साथ भोजन करे। देश के लिए जीने और मरने का संकल्प ही हर संकट का समाधान है।'

— मोहन भागवत, सरसंघचालक

PM-Kisan 22वीं किस्त : राजस्थान के 74 लाख किसानों में जगी उम्मीद, 13 मार्च को आ सकती है खुशखबरी

प्रधानमंत्री के असम दौरे पर टिकीं करोड़ों किसानों की नजरें, होली के बाद अब 'उपहार' का इंतजार

जयपुर (विशेष संवाददाता)। देशभर के करोड़ों किसानों के साथ-साथ राजस्थान के 74 लाख लाभार्थी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है। होली का त्योहार बीतने के बाद अब चर्चा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की 22वीं किस्त जल्द ही जारी की जा सकती है।

सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 13 मार्च 2026 वह संभावित तारीख हो सकती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीबीटी (DBT) के माध्यम से किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे।

13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के कोकराझार के दौरे पर रहेंगे। वहाँ वे बोडोलैंड टेरीटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि कोकराझार की इसी बड़ी जनसभा से पीएम मोदी देश के पात्र किसानों के लिए 22वीं किस्त का बटन दबा सकते हैं। हालांकि, अभी तक कृषि मंत्रालय या पीएमओ द्वारा इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई गई है।

यदि पिछले साल के आंकड़ों पर गौर करें, तो केंद्र सरकार हर चार महीने के अंतराल पर यह सहायता राशि जारी करती है।

20वीं किस्त : 2 अगस्त 2025 (वाराणसी, उत्तर प्रदेश से जारी)।
21वीं किस्त : 19 नवंबर 2025 (कोयंबटूर, तमिलनाडु से)।
22वीं किस्त : 13 मार्च 2026 (संभावित तिथि)।

कहीं आपकी किस्त रुक न जाए : भले ही 13 मार्च की तिथि संभावित हो, लेकिन किस्त पाने के लिए किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके दस्तावेज़ पूरी तरह दुरुस्त हैं। सरकार ने अपात्र लोगों को बाहर निकालने के लिए वेरिफिकेशन सख्त कर दिया है-

e-KYC अनिवार्य : जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनकी किस्त अटक सकती है। इसे पीएम-किसान पोर्टल या नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर पूरा किया जा सकता है।

लैंड सीडिंग (Land Seeding) : बैंक खाते के साथ भूमि रिकॉर्ड का सत्यापित होना जरूरी है।

आधार लिंकिंग : आपका बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी के लिए इनेबल होना चाहिए।

निष्कर्ष : फिलहाल 13 मार्च की तारीख केवल एक प्रबल संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक पुष्टि के लिए pmkisan.gov. in पर नजर बनाए रखें या हेल्पलाइन नंबर 155261 पर संपर्क करें।

जनवरी में एक कार चालक गवां चुका जान

प्रशासन और माफिया की मिलीभगत से बूंदी के डाबी क्षेत्र में खूनी खेल

हाईवे किनारे 'मौत' की ब्लास्टिंग : एनएच-27 पर नियमों को ताक पर रखकर खनन

बूंदी (विशेष संवाददाता)। बूंदी जिले का डाबी क्षेत्र, जो अपने विश्व प्रसिद्ध सेंड स्टोन के लिए जाना जाता है, अब अवैध खनन और जानलेवा ब्लास्टिंग का केंद्र बन गया है। नेशनल हाईवे 27 (कोटा-चित्तौड़ मार्ग) पर पराना रोड स्थित सर्विस रोड के किनारे तमाम नियम-कायदों को ताक पर रखकर खुलेआम खनन कार्य किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जहाँ नियम सड़क की सीमा से 100 मीटर तक खनन की अनुमति नहीं देते, वहीं यहां महज 50 मीटर की दूरी पर ही गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं।

जनवरी में गई थी एक निर्दोष की जान : खनन माफियाओं के दुस्साहस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेशनल हाईवे पर आवागमन के दौरान ही ब्लास्टिंग की जाती है। पिछले जनवरी माह में कुंभ मेले के लिए गुजरात से जा रहे एक कार चालक की मौत उस समय हो गई, जब ब्लास्टिंग के कारण एक बड़ा पत्थर उसकी कार के शीशे को तोड़कर अंदर जा घुसा। इस हादसे में अन्य यात्री भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस दर्दनाक घटना के बावजूद खनिज विभाग और खान सुरक्षा विभाग ने केवल खानापूर्ति करते हुए कुछ खानों को सीज कर अपनी इतिश्री कर ली।

नियमों की उड़ रही धज्जियां : सरकार और एनजीटी के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि हाईवे या मुख्य सड़कों के किनारे सुरक्षा घेरा होना चाहिए, लेकिन यहां स्थिति इसके उलट है।

दूरी का उल्लंघन: नियमों के अनुसार नेशनल हाईवे की सीमा से 100 मीटर तक खनन प्रतिबंधित है, लेकिन यहां सर्विस रोड के बिल्कुल करीब काम चल रहा है।

ब्लास्टिंग के नियम: हाईवे के 500 मीटर के दायरे में ब्लास्टिंग के लिए विशेष अनुमति और सुरक्षा आकलन अनिवार्य है, जिसका यहां पूर्णत: अभाव है।

गहराई बनी काल: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी डाबी-थड़ी सड़क के दोनों किनारों पर सैकड़ों फीट गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं, जहाँ सुरक्षा के नाम पर केवल पत्थर के बड़े ब्लॉक रख दिए गए हैं।

मिलीभगत का खेल: क्षेत्र में चर्चा है कि अजमेर मंडल खान सुरक्षा विभाग और स्थानीय खनिज विभाग के अधिकारियों की माफियाओं के साथ गहरी साठगांठ है। अधिकारियों को मासिक 'राजस्व' समय पर पहुँच जाता है, इसलिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती। आरोप है कि किसी भी निरीक्षण या कार्यवाही से पहले ही ठेकेदारों को सूचना दे दी जाती है, जिससे वे सतर्क हो जाते हैं। राजनैतिक दबाव के चलते जिला प्रशासन भी इस ओर से आँखें मूंदे बैठा है।

क्या कहते हैं अधिकारी ?

जब इस संबंध में बूंदी के खनिज अभियंता पी.एल. सोराया से संपर्क किया गया, तो उन्होंने नियमों और ईसी (श्वष्ट) की जानकारी तो साझा की, लेकिन मौके पर हो रहे अवैध खनन और अब तक की गई प्रभावी कार्यवाही पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।

यूडीए व वन विभाग की मिलीभगत का खेल | सज्जनगढ़ ईको सेंसिटिव जोन में 300 करोड़ के फर्जीवाड़े का मामला

पीएमओ का भी डर नहीं, तथ्यों को छुपाकर जांच में लीपापोती का खेल

जयपुर (विशेष संवाददाता)। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के ईको-सेंसिटिव जोन को संरक्षित करने के सरकारी दावों की धज्जियां खुद सरकारी महकमें ही उड़ा रहे हैं। उदयपुर विकास प्राधिकरण और वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से कालारोही गांव में नियमों को ताक पर रखकर खड़े किए जा रहे अवैध रिसार्ट के मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत पहुंची थी, जिस पर पीएमओ की ओर से उदयपुर कलक्टर व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उक्त फर्जीवाड़े और अनियमितताओं के गंभीर प्रकरण में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ ही उक्त अवैध निर्माण पर रोक लगाने की बजाए इस मामने में लीपापोती का खेल शुरू हो गया है। जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों को पीएमओ का भी कोई डर नहीं है, बल्कि मिलीभगत से तेजी से अवैध रिसार्ट का निर्माण कार्य पूरा करवाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में लगभग 300 करोड़ के वारे-न्यारे का खेल खेला गया है और रसूखदारों को मोटा फायदा पहुंचाया गया है।

दूरी में हेरफेर कर हासिल किया पट्टा : नियमानुसार एक किलोमीटर की परिधि में व्यावसायिक निर्माण वर्जित है, लेकिन वन विभाग और यूडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से इस ईको-सेंसिटिव जोन की भूमि आराजी नं. 3347-3350, 3333, 1391 व 1399 को मौका रिपोर्ट में 1050 मीटर दूर बता दिया गया। इस झूठी रिपोर्ट के आधार पर उदयपुर विकास प्राधिकरण ने पट्टा जारी करते हुए रिसार्ट के निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी, जो कि फर्जीवाड़े और मिलीभगत के बड़े खेल का उजागर करता है।

निर्माण में भी हेराफेरी, 2 की जगह 4 मंजिल का किया निर्माण : उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से रिसार्ट निर्माण के लिए 2 मंजिल की अनुमति जारी की गई थी, लेकिन रिसार्ट मालिक ने मौके पर मिलीभगत का पूरा फायदा उठाते हुए 4 मंजिल का अवैध निर्माण कर दिया। यूडीए अधिकारियों को 2 मंजिल का अवैध निर्माण अस्थाई ढांचा नजर आ रहा है, जबकि मौके पर 4 मंजिल की पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई है। निर्माण स्वीकृति के अनुसार मौके पर मात्र 96 हजार वर्ग फीट का निर्माण कराया जा सकता है, लेकिन रिसार्ट मालिक ने मौके पर 4 लाख वर्ग फीट से ज्यादा का पक्का निर्माण कर लिया गया है, जो कि यूडीए अधिकारियों को नजर नहीं आ रहा है।

नियमों की ऐसी उड़ी धज्जियां (तुलनात्मक विवरण)

मानक	नियम (ESZ)	मौके की स्थिति	उल्लंघन
ग्राउंड कवरेज	अधिकतम 20% (52,000 ft)	75% (1,50,000 ft)	300% ज्यादा
कुल निर्माण	96,000 sq. ft	4,00,000 sq. ft	विशालकाय अतिक्रमण
ऊंचाई/मंजिल	G+2 (दो मंजिल)	G+4 (चार मंजिल)	नियम विरुद्ध
हरियाली क्षेत्र	80% अनिवार्य	मात्र 15% शेष	पर्यावरण विनाश

जांच के नाम पर कागजी खानापूर्ति का खेल

ईको सेंसिटिव जोन के साढ़े 800 मीटर परिधि में चल रहे इस अवैध रिसोर्ट निर्माण के प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जिला कलक्टर उदयपुर व प्रधान मुख्य वन संरक्षक को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया था, जिसके बाद लग रहा था कि इस अवैध निर्माण पर रोक लगने के साथ ही नियम विरूद्ध अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन यूडीए व वन विभाग के अधिकारी अपने मिलीभगत के इस खेल को छुपाने के लिए मामले की लीपापोती में जुटे हुए हैं। जबकि कालारोही की इस आराजी भूमि पर हो रहा निर्माण न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, बल्कि यह एक आपराधिक कृत्य भी है।

समाचार पत्र 'द पब्लिक हब' के समस्त संपादकीय एवं प्रकाशकीय विषयों पर स्वायत अधिकार सहित प्रकाशक, स्वामी व संपादक: दीपक गोस्वामी,
ए-101 यूनिक टावर, प्रताप नगर, जयपुर-302017, मो. 9828528666 मुद्रक: अम्बर ऑफसेट प्रा. लि., जयपुर info@thepublichub.in, digital@thepublichub.in,
*पीआरबी एक्ट के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार।